● वर्ष-5

● अंक-241

रायपुर, मंगलवार
26 मई 2026

● पृष्ठ-8

● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8› आदिवासी संग्रहालय के विकास और...

भागवत के दौरे से ट्रिपल एस मॉडल को धार

संघ फिर तैयार करेगा यूपी में चुनावी जमीन

नईदिल्ली। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी सियासी एक्सरसाइज शुरू कर दी है। यूपी की सियासी तपिश के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ के दौरे पर पहुंचे हैं, जिसे लेकर सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं।

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत रविवार की शाम तीन दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे। संघ प्रमुख आरएसएस भले ही पूर्वी क्षेत्र के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने के लिए आए हों, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले उनके इस दौरे के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं।

मोहन भागवत के तीन के लखनऊ प्रवास को विशुद्ध रूप से आरएसएस के कार्यक्रम से जुड़ा बताया जा रहा है। प्रशिक्षण वर्ग में बौद्धिक निर्देशन के साथ ही संघ के शताब्दी वर्ष और विभिन्न अभियानों की समीक्षा करेंगे, लेकिन संघ प्रमुख की इस यात्रा ने प्रदेश की सियासी सरगर्मी को बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश को देश की %सत्ता का प्रवेश द्वार% कहा जाता है। यूपी की सियासत में आरएसएस की भूमिका हमेशा से एक %साइलेंट किंगमेकर% और %ग्राउंड इंजीनियर% की रही है। भले ही संघ खुद को एक सांस्कृतिक संगठन कहता

है, लेकिन बीजेपी के लिए जनसंघ के दौर से ही सियासी रण में वो मददगार बनता रहा है। 2017 और 2022 में बीजेपी को मिली जीत में संघ का रोल काफी अहम रहा है। ऐसे में 2027 से पहले मोहन भागवत एक बार फिर से यूपी पहुंचे हैं।

संघ प्रमुख मोहन भागवत तीन दिन के लखनऊ दौरे पर हैं और निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में ठहरे हैं। वो मंगलवार तक लखनऊ में रहेंगे। लखनऊ में संघ का अवध, गोरक्ष, काशी और कानपुर प्रांत के स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। इस दौरान मोहन भागवत प्रशिक्षण वर्ग में बौद्धिक निर्देशन के साथ ही संघ के शताब्दी वर्ष और विभिन्न अभियानों की समीक्षा करेंगे।

मोहन भागवत पूर्वी क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ बैठकों में वह शताब्दी वर्ष के तहत चल रहे गृह संपर्क अभियान, हिंदू सम्मेलनों सहित विभिन्न अभियानों के अलावा शाखा विस्तार पर चर्चा करेंगे और आगे के अभियानों और कार्यक्रमों को लेकर निर्देश देंगे। हालांकि संघ प्रमुख अपने प्रवास के दौरान किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, लेकिन आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बीजेपी के प्रमुख पदाधिकारियों, सरकार के प्रतिनिधियों और संघ के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल हो सकते हैं।

सीएम से डिप्टीसीएम से होगी मुलाकात?

संघ प्रमुख मोहन भागवत से लखनऊ प्रवास के दौरान सरकार और बीजेपी नेता मुलाकात करने से भी पहुंच सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर डिप्टीसीएम केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक सहित यूपी सरकार के कई बड़े मंत्री मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पकंज चौधरी भी दिल्ली से लखनऊ पहुंच गए हैं। सरकार और बीजेपी संगठन के तमाम अहम लोग संघ प्रमुख से मिलने के लिए निराला नगर जा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में सरकार के कामकाज और 2027 विधानसभा चुनाव तैयारियों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। ऐसे में वह प्रदेश के राजनीतिक हालात की भी जानकारी ले सकते हैं और जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी देखा गया है कि संघ प्रमुख लखनऊ पहुंचे हैं तो सरकार से लेकर संगठन तक के लोग उनसे मिलने पहुंचते रहे हैं।

ट्रिपल एस मॉडल से सत्ता की हैट्रिक

यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से संघ प्रमुख मोहन भागवत प्रचारकों और प्रमुख पदाधिकारियों से प्रदेश की समाजिक और राजनीतिक स्थितियों के संबंध में भी फीडबैक लेंगे। बीजेपी संगठन और सरकार के प्रमुख पदाधिकारियों से मुलाकात में संगठन और सरकार के बीच समन्वय के मुद्दों पर भी बात हो सकती है। इसे ट्रिपल एस मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह मॉडल पूरी तरह सरकार, संगठन और संघ के तीन स्तंभों पर आधारित माना जाता है।

संघ विचारधारा और अनुशासित कैडर नेटवर्क देता है। बीजेपी का संगठन चुनावी लामबंदी और राजनीतिक रणनीति संभालता है। जबकि सरकार अपने कामकाज और योजनाओं के आधार पर जनता के बीच संदेश पहुंचाती है। ये तीनों जब एक ही दिशा में काम करते हैं तो बीजेपी की चुनावी मशीनरी काफी प्रभावी मानी जाती है। 2014 के बाद बीजेपी की चुनावी जीत में इस मॉडल की भूमिका को लेकर चर्चा होती रही है।

2027 की चुनावी जंग जीतने का प्लान

2027 चुनाव से पहले फिर के एक बार ट्रिपल एस के बीच तालमेल बैठकर सत्ता की हैट्रिक लगाने का प्लान है। इसीलिए होली के बाद से यूपी के अलग-अलग क्षेत्रों में संघ और बीजेपी के बीच समन्वय बैठकों की एक पूरी श्रृंखला चली। इन बैठकों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह हिस्सा लिए थे, जबकि संघ के क्षेत्रीय और प्रांत स्तर के प्रचारक भी बैठक में शिरकत करते थे।

राजनीतिक विश्लेषक इन बैठकों को सिर्फ नियमित संगठनात्मक संवाद नहीं मानते, बल्कि 2027 के चुनावों से पहले बीजेपी की चुनावी रणनीति का शुरुआती खाका खींचने की कवायद बताते हैं। हालांकि, यह है कि बीजेपी और संघ के बीच इस तरह की समन्वय बैठकें नई नहीं हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से एक साल पहले भी इसी तरह का संवाद अभियान चलाया गया था। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जमीन पर सियासी माहौल बनाने के लिए यह रणनीति अपनाई गई थी। संघ और बीजेपी के सियासी तालेमल से ही चुनावी जंग जीतने में सफल रही है।

भाजपा की सियासी प्रयोगशाला

उत्तर प्रदेश संघ की सियासी प्रयोगशाला रही है। 1984 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पूरे देश में महज 2 सीटों पर सिमट गई थी। इसके बाद संघ के तत्कालीन सरसंघचालक बालासाहब देवरस की रणनीति के तहत संघ परिवार (विशेषकर विश्व हिंदू परिषद) ने राम मंदिर आंदोलन की कमान संभाली। संघ ने इस आंदोलन के जरिए उत्तर प्रदेश के बिखरे हुए हिंदू समाज को एक वैचारिक सूत्र में पिरोया।

बदलाव के ऐतिहासिक दौर से गुजर रही है सेना: जनरल चौहान

नयी दिल्ली। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि सेना बदलाव के दौर से गुजर रही है और इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच एकीकरण को मज़बूत करना, संचालन तालमेल को बढ़ाना और भविष्य की युद्ध संबंधी ज़रूरतों के हिसाब से क्षमताएं विकसित करना है।जनरल चौहान ने सोमवार को यहां मानेकशॉ सेंटर में मुख्यालय , एकीकृत स्टाफ और सैन्य मामलों के विभाग के जूनियर कमीशन अधिकारियों (जेसीओ), अन्य रैंकों (अन्य) और सिविल स्टाफ़ को संबोधित करते हुए एकीकरण, आत्मनिर्भरता और नवाचार को सशस्त्र बलों में चल रहे बदलाव के मार्गदर्शक स्तंभ करार दिया। इस संवाद के दौरान जनरल चौहान ने कहा कि भारतीय सेना बदलाव के ऐतिहासिक दौर से गुज़र रही है, जिसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच एकीकरण को मज़बूत करना, ऑपरेशनल तालमेल को बढ़ाना और भविष्य की युद्ध संबंधी ज़रूरतों के हिसाब से क्षमताएं विकसित करना है।प्रमुख रक्षा अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि केवल संस्थागत सुधारों से ही अपेक्षित बदलाव हासिल नहीं किया जा सकता और इस प्रक्रिया की सफलता हर स्तर पर मौजूद कर्मियों के समर्पण, पेशेवर रवैये और सक्रिय भागीदारी पर भी उतनी ही निर्भर करती है।

रायपुर। प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम, आबकारी व श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने आज सोमवार को नगर पालिक निगम कोरबा के सर्वमंगलानगर जोनांतर्गत विकास नगर में आयोजित सुशासन तिहार शिविर को संबोधित करते हुये आज कहा कि प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर जनसमस्याओं के निराकरण हेतु सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है। >>विस्तृत समाचार पेज- 8 पर

आधुनिक खेती से बदलेगा हर किसान भविष्य: अमित शाह

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इफको की 55वीं एजीएम में किसानों की समृद्धि और कृषि आधुनिकीकरण के लिए सरकार के प्रयासों को रेखांकित किया। पीएम-किसान, डिजिटल कृषि और नैनो यूरिया जैसे नवाचारों पर दिया जोर।

केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार किसानों की समृद्धि और कृषि के आधुनिकीकरण के लिए प्रभावी उपाय कर रही है। उन्होंने यह बात सोमवार को आयोजित इफको की 55वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के अवसर पर अपने लिखित संदेश में कही।शाह ने देश के सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) के प्रयासों की सराहना की, और उर्वरक तथा कृषि क्षेत्र के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को भी सराहा। यह संदेश इफको की तरफ से एक सोशल मीडिया मंच पर साझा किया गया है।

प्रमुख समाचार

बकरीद से पहले सीएम योगी के यूपी में सख्त निर्देश

लखनऊ। देशभर में ईद-उल-अधा (बकरीद) की तैयारियां ज़ोरों पर हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहार से पहले सख्त निर्देश जारी किए हैं। रविवार को हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने राज्य भर के पुलिस अधिकारियों और जिला मजिस्ट्रेटों को सतर्क रहने और त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी ने आदेश दिया है कि ईद-उल-अधा के दिन खुले स्थानों पर न तो नमाज़ पढ़ी जाएगी और न ही कुर्बानी दी जाएगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी ने बकरीद के उत्सव से संबंधित 10 सख्त निर्देश जारी किए हैं; आइए इन पर विस्तार से नज़र डालते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिया कि नमाज़ केवल मस्जिद परिसर के अंदर ही अदा की जानी चाहिए और किसी भी परिस्थिति में खुले सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज़ नहीं अदा की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि नमाज़ अदा करने के लिए सड़कों को अवरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए।

शिक्षा मंत्री तुरंत इस्तीफा दें : जयराम रमेश

नईदिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए, कांग्रेस राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने सोमवार को सीबीएसई की कक्षा 12 की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में कथित अनियमितताओं के लिए सरकार से जवाबदेही की मांग की। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री मोदी से यह स्पष्ट करने को कहा कि शिक्षा मंत्री की अक्षमता को इतने लंबे समय तक क्यों जारी रहने दिया गया। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि सीबीएसई ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम (ओएसएम) लागू किया है, जिससे देशभर के लाखों बच्चों का शैक्षणिक भविष्य अधर में लटक गया है। कांग्रेस सांसद ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की अपनी मांग दोहराई और प्रधानमंत्री से इस तरह की अक्षमता को जारी रहने देने पर सवाल उठाया। उन्होंने लिखा कि मंत्री प्रधान को देश को अपना इस्तीफा देना चाहिए।

बीजू जनता दल के राज्यसभा सांसद देबाशीष ने दिया इस्तीफा

कटक। ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक को झटका लगा है। बीजू जनता दल के राज्यसभा सांसद देबाशीष सामंतराय ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने पार्टी के भीतर उपेक्षा और अपमान का हवाला दिया। उन्होंने अपना त्यागपत्र बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को भेजा। सामंतराय ने कहा कि उन्हें व्यवस्थित रूप से अपमानित किया जा रहा है और पार्टी को अब उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। पटनायक को राज्यसभा के लिए मनोनीत करने और अविभाजित कटक और ओडिशा के लोगों की राष्ट्रीय स्तर पर सेवा करने का अवसर देने के लिए आभार व्यक्त किया। 25 मई, 2026 को लिखे अपने पत्र में सामंतराय ने लिखा कि उन्होंने हमेशा दृढ़ विश्वास और प्रतिबद्धता के साथ पार्टी के लिए काम किया है, लेकिन जनहित में पद छोड़ने का निर्णय लिया है। उन्होंने इस निर्णय को कठिन लेकिन आवश्यक बताया। मैंने हमेशा पार्टी के हित में स्वयं को समर्पित किया है।

हिमंत सरकार ने विधानसभा में पेश किया यूसीसी बिल

गुवाहाटी। असम कैबिनेट की मंजूरी के ठीक दो हफ्ते बाद राज्य सरकार ने सोमवार को विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पेश कर दिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की ओर से संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने सदन के पटल पर द यूनिफॉर्म सिविल कोड, असम, बिल, 2026 पेश किया। इस बेहद अहम विधेयक पर 27 मई को चर्चा और इसे पारित किए जाने की संभावना है। हालांकि, विपक्षी विधायकों ने असम विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश किए जाने का विरोध किया है। विपक्ष का कहना है कि इसे प्रस्तुत करने से पहले हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा होनी चाहिए। इससे पहले 13 मई को मुख्यमंत्री सरमा के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक हुई थी। तब सरकार ने घोषणा की थी कि 21 से 26 मई तक चलने वाले मौजूदा विधानसभा सत्र के दौरान यह कानून लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा था कि कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता के मसौदे को मंजूरी दे दी है, जिसे सत्र के अंतिम दिन पेश किया जाएगा।

कर्नाटक मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की तैयारी

बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया 26 मई को नई दिल्ली की यात्रा पर जा रहे हैं, जहां वे कांग्रेस के उच्च कमान के नेताओं- सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और केसी वेणुगोपाल - के साथ उच्च स्तरीय विचार-विमर्श करेंगे। इस यात्रा को राज्य के राजनीतिक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री मुख्य रूप से पार्टी नेतृत्व से अपने मंत्रिमंडल में बहुप्रतीक्षित फेरबदल के लिए मंजूरी लेंगे, और यह पहला बड़ा फेरबदल होगा। प्रस्तावित फेरबदल से सरकार में बेहतर प्रतिनिधित्व और प्रदर्शन-आधारित बदलावों की लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करने की उम्मीद है। मंत्रिस्तरीय फेरबदल के अलावा, राज्यसभा चुनावों के लिए तीन उम्मीदवारों के नामों और विधान परिषद के लिए नामांकनों पर भी चर्चा होने की संभावना है। एमएलसी चुनाव के बाद, कांग्रेस ऊपरी सदन में सबसे बड़ी पार्टी होगी और अगले अध्यक्ष के भी इसी पार्टी से होने की संभावना है। ये नियुक्तियाँ परिषद में पार्टी की उपस्थिति को मजबूत करने और महत्वपूर्ण चुनावी मुकाबलों से पहले वफादारों को पुरस्कृत करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।

पद्म पुरस्कार 2026

धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण, 131 हस्तियों को पद्म सम्मान

नईदिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक नागरिक अलंकरण समारोह में बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र और शास्त्रीय संगीतकार एवं वायलिन वादक एन राजम को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया। कला के क्षेत्र में असाधारण एवं विशिष्ट योगदान के लिए धर्मेंद्र को दिया गया यह पुरस्कार उनकी पत्नी और सांसद हेमा मालिनी ने ग्रहण किया। राजम को भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके अहम योगदान के लिए, खासकर 'गायकी अंग' शैली के माध्यम से वायलिन प्रस्तुति को नया स्वरूप प्रदान करने के लिए दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। राजम ने पंडित ओंकारनाथ ठाकुर से संगीत के गुर सीखे थे।

मुर्मू ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी; चुनौतियों का सामना कर रहे पारंपरिक भारतीय कला 'अवधान'को पुनर्जीवित करने वाले शतावधानी आर गणेश; कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय सुरेश कुमार कोटक; और उदर रोग विशेषज्ञ कल्लीपट्टी रामासामी पलानीस्वामी को पद्म भूषण से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने विज्ञापन गुरु पीयूष पांडे और पूर्व सांसद विजय कुमार मल्होत्रा को भी मरणोपरांत इस सम्मान से नवाजा। पांडे की पत्नी और मल्होत्रा के बेटे ने सम्मान प्राप्त किया।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भुल्लर, अभिनेता प्रोसेनजीत चटर्जी, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के पूर्व महानिदेशक के. विजय कुमार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में हुए इस समारोह की शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन से हुई, जिसके बाद राष्ट्रगान 'जन गण मन' गाया गया। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए।

राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कार देने की मंजूरी दी है। इनमें पांच पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री शामिल हैं। ये पुरस्कार दो अलग-अलग अलंकरण समारोहों में प्रदान किये जाने हैं। पद्म पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर की जाती है। ये प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल और सिविल सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रदान किये जाते हैं।

कला और संस्कृति के योगदान को मिला राष्ट्रीय सम्मान

पद्म पुरस्कार केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों का सम्मान नहीं हैं, बल्कि वे भारत की सांस्कृतिक, कलात्मक और रचनात्मक विरासत को भी सम्मानित करते हैं। इस वर्ष सम्मानित होने जा रही फिल्म और संगीत जगत की हस्तियां उन कलाकारों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिन्होंने दशकों तक अपनी प्रतिभा, समर्पण और सृजनशीलता से भारतीय समाज को समृद्ध बनाया है। पद्म पुरस्कार 2026 एक बार फिर यह संदेश देता है कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तित्व राष्ट्र की अमूल्य धरोहर हैं।

खाद-बीज का पर्याप्त भंडारण एवं अग्रिम उठाव कराने कलेक्टर ने दिए निर्देश

उत्तर बस्तर कांकेर। कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने सोमवार को आयोजित समय-सीमा की बैठक में कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले में आगामी खरीफ सीजन के लिए खाद-बीज का पर्याप्त भंडारण किया जाकर किसानों को अग्रिम उठाव के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने इस कार्य की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी कृषि विभाग के उप संचालक को दिए हैं। समीक्षा के दौरान उप संचालक ने बताया कि जिले के किसानों द्वारा खाद-बीज का उठाव प्रारंभ कर दिया गया है। कलेक्टर ने जिले में संचालित निर्माण कार्यों को समय-सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश भी दिए। उचित मूल्य दुकानों के लिए भवनों का निर्माण बारिश के पूर्व करने तथा पहुंचविहीन क्षेत्रों में खाद्यान्न का अग्रिम भंडारण करने के लिए निर्देशित किया गया। दूरसंचार टॉवर की स्थापना कार्य की समीक्षा भी उनके द्वारा की गई एवं सभी एसडीएम को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। आगामी मानसून को दृष्टिगत रखते हुए मौसमी बीमारियों पर सतत निगरानी एवं त्वरित उपचार के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए गए। मनरेगा के अंतर्गत संचालित सभी कार्यों को 30 जून तक अनिवार्य रूप से पूरा करने कहा गया। बैठक में जिला पंचायत के सीईओ श्री हरेश मंडावी, अपर कलेक्टर श्री जितेन्द्र कुर्रे एवं श्री ए.एस. पैकरा, सभी एसडीएम, विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी, जनपद सीईओ एवं नगरीय निकायों के अधिकारी मौजूद थे।

स्क्रीनिंग चेंबर एंड प्लांटेड ड्राइंग बेड निर्माण में भ्रष्टाचार

दीवारों पर दरारें-सूचना पटल गायब

तखतपुर। तखतपुर क्षेत्र में लाखों रुपए की लागत से बनाए गए स्क्रीनिंग चेंबर एंड प्लांटेड ड्राइंग बेड निर्माण कार्य में भारी भ्रष्टाचार और अनियमितता का मामला सामने आया है। मौके पर जमीनी पड़ताल में निर्माण कार्य की गुणवत्ता बेहद खराब मिली, जबकि जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कार्य का मूल्यांकन सत्यापन कर ठेकेदार को लगभग 30 लाख रुपए से अधिक का भुगतान भी कर दिया गया।

जानकारी के मुताबिक, निर्माण स्थल पर बनाए गए टैंकों में कई जगह गुणवत्ताहीन कार्य दिखाई दे रहा है। दीवारों और प्लास्टर में दरारें, अधूरापन और घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य शुरू से ही सवालों के घेरे में था, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने जांच करने के बजाय आंख मूंदकर भुगतान कर दिया। सबसे हैरानी की बात यह है कि लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद इस योजना का उपयोग लगभग शून्य है। जिस उद्देश्य को लेकर यह निर्माण कराया गया था, वह आज तक पूरा नहीं हो सका। योजना केवल कागजों और भुगतान फाइलों तक सीमित होकर रह गई है।

निर्माण कार्य में पारदर्शिता के नियमों की भी खुलकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। आठ निर्माण कार्यों में लगाए जाने वाले नागरिक सूचना पटल में भी गड़बड़ी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक केवल तीन स्थानों पर सूचना पटल लगाए गए, जबकि बाकी जगहों पर सिर्फ दीवार लेखन कर औपचारिकता निभा दी गई।

बता दें कि पूर्व में जनपद पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने निर्माण कार्यों में सूचना पटल नहीं लगाए जाने को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया।

तखतपुर क्षेत्र में लगातार निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोप सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या जिम्मेदार अधिकारियों की मौन सहमति से ही घटिया निर्माण और भुगतान का खेल चल रहा है। अब देखना यह होगा कि लाखों रुपए की इस योजना में सामने आए भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोपों पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा।

वही इस मामले के संबंधित एस डी ओ रघुवीर साहू से ग्रामीण यांत्रिकी कार्यालय जाकर जानकारी लेने की कोशिश की गई, लेकिन इस विषय में जानकारी देने से बचते रहे और मीडिया में बोलने से इंकार करते रहे। इस मामले को लेकर बिलासपुर कार्यपालन अभियंता (ई ई) पी एल पडवार ने संबंधित स्ठह से जानकारी लेने की बात कही है।

सब्जी के कैरेट में छिपाकर ले जा रहे थे 65 लाख का गांजा जब्त

गरियाबंद। गरियाबंद की देवभोग पुलिस को गांजा तस्करी के मामले में एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 130 किलो गांजा बरामद किया है, जिसे सब्जी के कैरेट में छुपाया गया था और ओड़िशा से उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था। पकड़े गए गांजे की कीमत 65 लाख रुपए आंकी गई है। यह मामला देवभोग थाना क्षेत्र का है। दरअसल, पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ओडिशा की ओर से एक संदिग्ध वाहन भारी मात्रा में मादक पदार्थ लेकर उत्तर प्रदेश की तरफ निकलने वाला है। सूचना के आधार पर देवभोग पुलिस ने खुटगांव चेकपोस्ट पर घेराबंदी कर वाहनों की कड़ाई से जांच शुरू की। इसी दौरान एक गाड़ी को रोका गया, जिसमें ऊपर से सब्जी के कैरेट लदे हुए थे। जब पुलिस ने बारीकी से तलाशी ली, तो सब्जी के कैरेटों के नीचे छिपाकर रखे गए गांजे के पैकेट बरामद हुए। पुलिस ने मौके से ही तस्करी कर रहे आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जिसने अपना नाम राहुल पांडेय बताया और वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट (NDPS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि ओडिशा में यह माल किसने सप्लाई किया था और यूपी में इसे कहां खपाया जाना था।

बता दें कि सप्ताहभर के भीतर पुलिस की यह तीसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले भी पुलिस ने ओडिशा सीमा पर मुस्तैदी दिखाते हुए मध्य प्रदेश (स्क्क) के तस्करों को दबोचा था, जिनसे 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का गांजा बरामद किया गया था।

मुरूम का अवैध खनन कर रही सेल्के कंपनी, गांवों की सरकारी जमीन खाई में तब्दील

अभनपुर। क्षेत्र के गांवों में सेल्के कंपनी नियमों को ताक पर रखकर दो चेन माउंटेन मशीनों से मुरूम का अवैध उत्खनन कर रही है। वहीं रहवासी इलाके से ओवरलोड 16 चक्का वाहनों से मुरूम का परिवहन किया जा रहा है। इसके चलते ग्राम खोला को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसके कारण आने-जाने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों में कंपनी के खिलाफ भारी आक्रोश देखा जा रहा है। ठेलकाबांधा में कंपनी सरकारी जमीन को इस तरह खोद रही है कि मानो वह उनकी निजी जमीन है। गांव की जमीन को मौत के कुएं में तब्दील कर दिया गया है। अवैध खनन से 25 से 30 फीट खाई बना दी गई है, लेकिन खनिज विभाग के अधिकारी सोए हुए हैं। बताया जाता है कि कंपनी द्वारा रायल्टी से 100 गुना मुरूम निकाली गई है। रायल्टी 10 घनमीटर के लिए है और 16 चक्का ट्रक में 40 घनमीटर मुरूम का अवैध परिवहन कर रहे हैं। कंपनी द्वारा ग्राम खोरपा एवं संकरी में भी 30 से 40 फीट गहराई कर अवैध मुरूम निकाली गई है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे के रायपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष माखन ताम्रकार ने कहा कि सेल्के कंपनी पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो इस मुद्दे को लेकर एसडीएम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शासकीय घास जमीन को कंपनी द्वारा गांव-गांव में मौत का कुआं बना दिया गया है। कार्रवाई नहीं होने से सेल्फे कंपनी के हौसले बुलंद है। एसडीएम रवि सिंह ने कहा, कई गांव से कंपनी की शिकायत आ रही है। रायल्टी कितने की ली है और कितना घनमीटर खोदाई कर लिया गया है, इनकी जांच की जाएगी। इसके बाद सेल्के कंपनी पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। मुरूम के अवैध उत्खनन की पटवारी रिपोर्ट के आधार पर कंपनी को नोटिस जारी किया जाएगा। रायल्टी से अधिक मुरूम की कंपनी भरपाई करेगी।

15 हजार रिश्वत लेते पटवारी को एसीबी ने रंगे हाथों दबोचा

बेमेतरा। जिले के साजा ब्लॉक मुख्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पटवारी ओंकार सुनवानी को 15 हजार रुपए नगद रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। जानकारी के अनुसार, ग्राम केंद्र निवासी किसान नरोत्तम अपने जमीन संबंधी कार्य को लेकर लगातार पटवारी कार्यालय के चक्कर काट रहा था। आरोप है कि काम करने के एवज में पटवारी ने रिश्वत की मांग की थी। सौदा 30 हजार रुपए में तय हुआ, जिसमें पहली किस्त के रूप में 15 हजार रुपए दिए जाने थे। किसान ने मामले की शिकायत एसीबी से की थी। शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी की टीम ने जाल बिछाया। जैसे ही किसान ने पटवारी को 15 हजार रुपए दिए, टीम ने मौके पर दबिश देकर आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया। फिलहाल एसीबी की टीम पटवारी ओंकार सुनवानी से पूछताछ कर रही है। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

सामूहिक भोज के बाद 17 ग्रामीण हुए बीमार, एक महिला की मौत

कोंडागांव। जिले के तमरावंड क्षेत्र में आयोजित सामूहिक भोज उस वक्त मातम में बदल गया, जब भोजन करने के बाद अचानक लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। उल्टी-दस्त और पेट दर्द की शिकायत के बाद एक-एक कर 17 लोगों को अस्पताल पहुंचाना पड़ा। इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जबकि अन्य मरीजों का उपचार जारी है। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार, गांव में आयोजित सामूहिक भोज में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए थे। भोजन करने के कुछ घंटों बाद लोगों को उल्टी, चक्कर और तेज पेट दर्द की शिकायत शुरू हुई। देखते ही देखते कई लोग बीमार पड़ गए। ग्रामीणों ने तत्काल बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने फूड प्वाइजनिंग की आशंका जताई है। घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम सक्रिय हुई। खाद्य विभाग ने भोज में परोसे गए भोजन के नमूने जांच के लिए भेज दिए हैं। वहीं प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुट गया है। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि भोजन में किस वजह से जहरीलापन फैला। एक महिला की मौत ने पूरे गांव को झकझोर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि किसी भी सामूहिक आयोजन में खास कर गर्मी के समय ताजा भोजन का ही सेवन करें। बासी भोजन से बचें। खाने की गुणवत्ता और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें एवं तबीयत बिगड़ने पर तुरंत अस्पताल पहुंचें।

सिविल सर्जन डॉ. टीएल मंडावी ने बताया कि कल तमरावंड गांव में देवी-देवताओं की पूजा के बाद सामूहिक भोजन का आयोजन किया गया था। भोजन करने के उपरांत कुछ लोगों की तबीयत अचानक खराब होने लगी। इस घटना में एक महिला की मौत हुई है, जबकि 9 लोगों का इलाज अस्पताल में जारी है। प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच में जुटा हुआ है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

ईंट से बजरंगबली की तोड़ी मूर्ति, ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल

गरियाबंद। फिंगेश्वर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भेन्डरी-जामगांव में असमाजिक तत्व ने भगवान की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया है। अज्ञात ने शराब सेवन के बाद बरंगबली की टाइल्स युक्त मूर्ति को खंडित कर दी। घटना से ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है। सूचना मिलने पर हिंदू संगठन मौके पर पहुंचे। मामला फिंगेश्वर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार, मंदिर परिसर के पास शराब सेवन और ईंट से मूर्ति तोड़ने के निशान मिले हैं। घटना की सूचना मिलते ही विहिप जिला संयोजक मोहित साहू और फिंगेश्वर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। विहिप जिला संयोजक मोहित साहू ने घटना की निंदा करते हुए मामले में आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं रविवार को ग्राम समिति अध्यक्ष भेखलाल साहू के नेतृत्व में ग्रामीणों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें गांव के लोगों से घटना के संबंध में जानकारी ली गई। बैठक में किसी ग्रामीण के इस घटना में शामिल होने की बात सामने नहीं आई। ग्रामीणों ने फिंगेश्वर थाना पहुंचकर शिकायत की

दूतकैया हिंसा केस- सर्व हिंदू समाज ने किया धरना प्रदर्शन

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के दूतकैया गांव में 1 फरवरी को हुई हिंसक घटना अब लगातार तूल पकड़ती जा रही है। रविवार को सर्व हिंदू समाज एवं ग्राम विकास समिति के बैनर तले ग्रामीणों ने राजिम के पंडित सुंदरलाल शर्मा चौक पर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपाकर पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए एसआई जीवन साहू को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। धरना प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करने के बजाय एक तरफा कार्रवाई कर रही है और निर्दोष ग्रामीणों को झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। ज्ञापन में कहा गया कि घटना के बाद गांव के युवाओं को जबरन हिरासत में लेकर उनके हाथों में डंडा, लाठी और तलवार पकड़ाकर फोटो खिंचवाए गए, ताकि उन्हें अपराधी साबित किया जा सके। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचनामा और अन्य कानूनी दस्तावेजों के नाम पर पुलिस की ओर से कोरे कागजों में हस्ताक्षर कराए गए।

पेंड्रा में पारा 42°C पहुंचा, लू के थपेड़ों से लोग बेहाल

गौरेला पेंड्रा मरवाही। नौतपा शुरू होते ही जिले में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिला। अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और रियल फील 45 डिग्री तक पहुंचने से लोग बेहाल हो गए, सड़कें सन्नाटे में बदल गईं और बाजारों में सन्नाटा पसर गया जिले में नौतपा के पहले दिन ही भीषण गर्मी का असर देखने को मिला। लगातार बढ़ते तापमान और गर्म हवाओं ने लोगों का जनजीवन प्रभावित कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार पेंड्रा क्षेत्र में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। वास्तविक अनुभव 45 डिग्री तक महसूस किया जा सकता है। सुबह से ही तेज धूप और उसम के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दोपहर होते-होते सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। बाजारों में भी लोगों की आवाजाही कम दिखाई दी। सबसे ज्यादा असर दिहाड़ी मजदूरों, राहगीरों और छोटे व्यापारियों पर पड़ रहा है। गर्म हवाओं और लू के थपेड़ों से लोग बेहाल नजर आए। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना जताई है।

झीरम कांड बरसी: फरसपाल से दंतेवाड़ा तक दी श्रद्धांजलि

दंतेवाड़ा। झीरम कांड और महेंद्र कर्मा की शहादत के 13 वर्ष पूरे हो गए हैं। बस्तर टाइगर के नाम से पहचान बनाने वाले स्व. महेंद्र कर्मा को आज भी लोग एक ऐसे जननेता के रूप में याद करते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बस्तर, आदिवासी समाज और क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित कर दिया। उनकी शहादत दिवस पर उनके गृह ग्राम फरसपाल सहित दंतेवाड़ा जिले के कई स्थानों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां हजारों लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। फरसपाल में आयोजित मुख्य श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कांग्रेस, भाजपा समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और आम नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने महेंद्र कर्मा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया तथा उनके संघर्ष, साहस और बस्तर के प्रति समर्पण को याद किया। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों की आंखें नम दिखाई दीं। लोगों ने कहा कि महेंद्र कर्मा केवल एक राजनीतिक नेता नहीं थे।

समाधान शिविर में ग्रामीणों को मिला योजनाओं का लाभ

बीजापुर। सुशासन तिहार के तहत कुटरु में एक समाधान शिविर आयोजित हुआ। भीषण गर्मी के बावजूद हजारों ग्रामीण इसमें शामिल हुए। ग्रामीणों ने शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लिया और अपनी समस्याएं बताईं। शिविर में गुदमा, कोमपल्ली, कुटरु सहित 18 से अधिक ग्राम पंचायतों के ग्रामीण पहुंचे। जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी कोरसा मुख्य अतिथि थीं। उन्होंने ग्रामीणों को योजनाओं का अधिक लाभ लेने को प्रेरित किया। महतारी वंदन, प्रधानमंत्री आवास, धान खरीदी और तेंदूपत्ता संग्रहण जैसी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बस्तर मुन्ने कार्यक्रम में सहयोग की अपील की। अधिकांश योजनाओं में राशि सीधे बैंक खातों में आती है। इसलिए बैंक खाता और आधार कार्ड आवश्यक बताया गया। आयुष्मान कार्ड से पांच लाख रुपये तक की निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा मिलती है। शिविर में 24 से अधिक विभागों ने स्टॉल लगाए। उन्होंने विभागीय योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया।

नक्सलवाद के साथ नक्सलवादी मानसिकता का खात्मा भी जरूरी

मनोज कुमार अग्रवाल

नक्सलवाद के लगभग पूरी तरह खत्म होने का दावा काफी हद तक सही है, क्योंकि हाल के वर्षों में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक जीत हासिल की है। सरकार द्वारा निर्धारित 31 मार्च, 2026 की समय-सीमा तक वामपंथी उग्रवाद को अपने सबसे मजबूत गढ़ों (जैसे बस्तर) से काफी पीछे धकेल दिया गया है।

नक्सलवाद की समाप्ति के दावों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि जमीनी कार्रवाई में बड़ी सफलतासुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियानों में भारी सफलता हासिल की है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले दो वर्षों में सैकड़ों कुख्यात नक्सली कमांडरों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है और हजारों नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। घटता दायरा (रेड कॉरिडोर)कभी देश के करीब 180 जिलों में फैला नक्सली प्रभाव अब सिमटकर बहुत ही कम क्षेत्रों (मुख्य रूप से दक्षिण छत्तीसगढ़ के अंदरूनी इलाकों) तक रह गया है। मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित किया जा चुका है लेकिन अभी नक्सली मानसिकता का समूल नष्ट करना बाकी है।

आपको बता दें कि भारत के लिए नक्सलवाद केवल कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं था, बल्कि यह देश की आंतरिक सुरक्षा, लोकतांत्रिक व्यवस्था और आदिवासी समाज के भविष्य से जुड़ा एक गहरा संकट था। दशकों तक नक्सल हिंसा ने देश के अनेक हिस्सों, विशेषकर छत्तीसगढ़ के बस्तर जैसे क्षेत्रों को भय, अविश्वास और पिछड़ेपन के अंधेरे में धकेले रखा। उससे मुक्ति निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त बताते हुए यह भी कहा कि अब सरकार की जिम्मेदारी पिछले 50 वर्षों के नुकसान की भरपाई करना है और बस्तर को देश के सबसे विकसित आदिवासी क्षेत्रों में शामिल करना है। सरकारी बयान के अनुसार, 3,000 आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों को सम्मानजनक जीवन देने और बस्तर को विकसित भारत की यात्रा से जोड़ने पर जोर दिया गया है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बस्तर से यह कहना कि भारत नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है, निस्संदेह एक ऐतिहासिक क्षण है। यह घोषणा केवल सरकार की उपलब्धि नहीं, बल्कि उन हजारों जवानों, पुलिसकर्मियों, स्थानीय आदिवासियों और निर्दोष नागरिकों के संघर्ष की परिणति है, जिन्होंने इस लंबी लड़ाई में अपनी जान, परिवार और भविष्य तक दांव पर लगा दिया। नक्सलवाद का इतिहास देश के लिए पीड़ा से भरा रहा है। 1970 के दशक से लेकर लंबे समय तक यह हिंसक विचारधारा गरीबों, आदिवासियों और वंचितों के नाम पर बंदूक की राजनीति करती रही। जिन लोगों के अधिकारों की बात कर नक्सल आंदोलन खड़ा किया गया था, सबसे अधिक नुकसान भी उन्हीं गरीबों और आदिवासियों को उठाना पड़ा।

स्कूल जलाए गए, सड़कें नहीं बनने दी गई, स्वास्थ्य केंद्रों का विरोध हुआ, सरकारी योजनाओं को गांवों तक पहुंचने से रोका गया और युवाओं को शिक्षा के बजाय हथियार थमा दिए गए।आपको पता है कि यह विडंबना ही थी कि विकास के नाम पर शुरू हुआ आंदोलन विकास का सबसे बड़ा विरोधी बन गया। बस्तर इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहा है। प्राकृतिक संपदा, आदिवासी संस्कृति और मानवीय संभावनाओं से भरपूर यह क्षेत्र लंबे समय तक भय का दूसरा नाम बना रहा। रात में आवाजाही चंद, गांवों में खामोशी, स्कूलों में ताले, सड़क निर्माण पर हमला और सुरक्षा बलों पर घात लगाकर वार, यह सब बस्तर की सामान्य पहचान बन चुका था। नक्सलियों के डर के कारण सरकारी योजनाएं कागजों में रह जाती थीं और आम आदिवासी नागरिक अपने ही देश की विकास यात्रा से कट जाता था। थान की खरीद, मुफ्त राशन, शिक्षा, नौकरी में आरक्षण, स्वास्थ्य रक्षण, स्वास्थ्य सुविधा और सड़क जैसी बुनियादी चीजें भी कई इलाकों में सपने जैसी थीं।

इसलिए जब गृह मंत्री ने कहा कि बस्तर के लिए यह बड़ा दिन है और देश नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है, तो यह बयान केवल राजनीतिक घोषणा नहीं माना जाना चाहिए। यह उन सुरक्षा बलों के परिश्रम की मान्यता है, जिन्होंने बेहद कठिन भौगोलिक परिस्थिति, जंगलों, पहाड़ियों और बारूदी सुरंगों के बीच संघर्ष किया। सीआरपीएफ, कोबरा कमांडो, डीआरजी, राज्य पुलिस और स्थानीय सुरक्षा बलों ने जिस साहस, धैर्य और रणनीति के साथ अभियान चलाए, यह भारत की आंतरिक सुरक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस सफलता में स्थानीय आदिवासी समाज की भूमिका भी कम नहीं है। जब स्थानीय जनता का भरोसा शासन और सुरक्षा बलों पर बढ़ता है, तभी किसी भी हिंसक आंदोलन की जमीन कमजोर होती है। नक्सलवाद के खिलाफ जीत केवल सैन्य या पुलिस कार्रवाई से संभव नहीं थी। इसकी असली सफलता सुरक्षा और विकास के संतुलित मॉडल में निहित है। यदि बंदूक के जवाब में केवल बंदूक होती, तो समस्या शायद कमजोर होती, लेकिन समास नहीं होती।

संक्षिप्त समाचार

छत्तीसगढ़ में इबोला वायरस को लेकर हाई अलर्ट! रायपुर एयरपोर्ट पर होगी यात्रियों की स्वास्थ्य जांच

रायपुर। दुनियाभर में तेजी से फैल रहे इबोला

संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, छत्तीसगढ़ की ओर से इबोला संक्रमण की रोकथाम को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य जांच, संदिग्ध मामलों की पहचान और आपातकालीन प्रबंधन व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा गया है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं के अंतर्गत एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) की ओर से जारी पत्र में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को एयरपोर्ट परिसर में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। जारी निर्देशों में कहा गया है कि एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य स्क्रीनिंग व्यवस्था का समन्वय सुनिश्चित किया जाए। साथ ही किसी भी संदिग्ध मरीज की पहचान होने पर तत्काल संबंधित स्वास्थ्य विभाग को सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने आइसोलेशन, रेफरल और आपातकालीन प्रबंधन व्यवस्था को भी पूरी तरह तैयार रखने कहा है, ताकि किसी भी संभावित स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। बता दें कि कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद दुनियाभर में सतर्कता बढ़ाई गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही इसे अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर चुका है।

नगरीय निकायों में 240 एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों में 392 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में चल रहे नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्रों की जांच, संवीक्षा एवं नाम वापसी की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। आयोग द्वारा जारी विस्तृत आंकड़ों के अनुसार नगरीय निकायों में कुल 240 तथा त्रि-स्तरीय पंचायतों में कुल 392 अभ्यर्थी चुनावी मैदान में उतरेंगे। त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के अंतर्गत पंच पद के लिए कुल 1136 पद निर्धारित थे, जिनमें 385 पदों पर कोई नामांकन प्राप्त नहीं हुआ तथा 4 पदों पर नामांकन निरस्त किए गए। 640 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ है, जबकि शेष 107 पदों पर मतदान कराया जाएगा, जिनके लिए कुल 246 उम्मीदवार मैदान में हैं। सरपंच पद के लिए कुल 82 पदों में से 30 पदों पर नामांकन प्राप्त नहीं हुए तथा 3 नामांकन निरस्त हुए। 15 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ है और शेष 34 पदों पर मतदान होगा, जहां कुल 105 अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे हैं। इसी प्रकार जनपद सदस्य के 10 पदों पर सभी स्थानों पर सविरोध निर्वाचन होगा तथा इन पदों के लिए कुल 41 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। नगरीय निकाय निर्वाचन के अंतर्गत पार्षद पद के कुल 71 स्थानों पर मतदान कराया जाएगा। इन पदों के लिए कुल 221 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। अध्यक्ष पद के 5 स्थानों पर भी निर्वाचन होगा, जिनके लिए कुल 19 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया है। इन पदों पर न तो कोई नामांकन निरस्त हुआ और न ही कोई निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ है।

आकस्मिक मृत्यु के दो प्रकरणों में 8 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत

रायपुर। जांजगीर-चांपा जिले में आकस्मिक आपदा मृत्यु के दो प्रकरणों में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत कुल 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील शिवरीनारायण अंतर्गत ग्राम करमंदी निवासी श्री सुमेश कुमार गहरे की पानी में डूबने से मृत्यु हो जाने पर उनकी पत्नी श्रीमती रेखा गहरे को 4 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार तहसील पामगढ़ के ग्राम चेऊडीह निवासी श्री संजय टंडन की लू लगने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी श्रीमती संगीता टंडन को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है।

एक खाद दुकान का लाइसेंस निलंबित, कई विक्रेताओं को नोटिस

रायपुर। धमतरी जिले में किसानों को निर्धारित दर पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। औचक निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर एक उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया, जबकि कई निजी और सहकारी विक्रय केन्द्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। विभाग ने साफ कर दिया है कि कालाबाजारी, अधिक कीमत व अनियमित बिक्री किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि विभाग की टीम लगातार जिलेभर में निरीक्षण कर रही है। उप संचालक कृषि, उर्वरक, बीज एवं कीटनाशी निरीक्षकों सहित विभागीय अधिकारियों ने धमतरी, कुरूद, मगरलोड और नगरी विकासखंड के कई सहकारी एवं निजी उर्वरक विक्रय केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया।

सड़क दुर्घटनाएं नहीं हों, इसके लिए हर जरूरी कदम उठाएं : मुख्य सचिव

■ ब्लैक स्पॉट की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश, प्रदेश में 150 स्थानों पर लगे ईव्ही चार्जिंग स्टेशन

रायपुर। मुख्य सचिव श्री विकासशील ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए सभी समुचित और ठोस कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। मुख्य सचिव आज मंत्रालय में सड़क सुरक्षा को लेकर आयोजित बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे।

मुख्य सचिव ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के लिए चिन्हित ब्लैक स्पॉट की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और वहां आवश्यक सुधार कार्य तत्काल किए जाएं। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय से सड़कों की स्थिति सुधारने के निर्देश दिए ताकि हादसों की आशंका खत्म हो सके।

बैठक में राज्य सड़क सुरक्षा कोष, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फलोदी एवं रंगा रेड्डी सड़क दुर्घटना मामलों में दिए गए दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। साथ ही पीएम राहत योजना और पीएम ई-ड्राईव योजना की प्रगति की जानकारी ली गई। मुख्य सचिव ने सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने को कहा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सड़क दुर्घटना रेस्क्यू से संबंधित एसओपी के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई।

मुख्य सचिव ने पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत ई-वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन की स्थापना में तेजी लाने को कहा। उन्होंने परिवहन विभाग को निर्धारित स्थलों पर तत्काल ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में अब तक 150 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं। इन स्टेशनों पर पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत सब्सिडी भी दी जाती है।

मुख्य सचिव ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को त्वरित उपचार मिलना सबसे जरूरी है। प्रधानमंत्री राहत योजना के तहत घायलों का अस्पताल में कैशलेस उपचार किया जाता है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, गृह-पुलिस, परिवहन तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि योजना के तहत अब तक 282 सड़क दुर्घटनाओं में घायलों के उपचार के लिए पंजीकरण किया गया है। मुख्य सचिव ने इस योजना के क्रियान्वयन की विस्तार से समीक्षा की और इसे और प्रभावी बनाने को कहा।

बैठक में परिवहन विभाग के सचिव एवं आयुक्त श्री एस. प्रकाश, नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव सुश्री आर. शंगीता सहित पुलिस, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने लिया डायल 112 का टेस्ट

खुद पीड़ित बनकर दर्ज कराई शिकायत

रायपुर। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ में आपातकालीन सेवाओं की जमीनी हकीकत और रिस्पांस टाइम परखने के लिए एक अनोखा कदम उठाया। उन्होंने खुद पीड़ित बनकर डायल 112 का टेस्ट लिया। शिकायत के बाद जैसी ही डायल 112 की गाड़ी मौके पर पहुंची, तो उन्होंने गाड़ी और उससे जुड़ी सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।

दरअसल, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा डायल 112 की कार्यप्रणाली को परखने के लिए खुद पीड़ित बन गए और अपनी शिकायत दर्ज कराई। विजय शर्मा ने डायल 112 को कॉल कर कहा कि बेमेतरा थाने के पास एक्सीडेंट हुआ है, जिसके लिए डायल 112 की जरुरत है। शिकायत के दर्ज होने के कुछ देर बाद मौके पर डायल 112 की गाड़ी पहुंच गई।

इसके बाद उन्होंने खुद गाड़ी और उससे जुड़ी सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वाहन में उपलब्ध तकनीकी सुविधाओं, लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस, रिस्पांस सिस्टम और आपातकालीन परिस्थितियों में पुलिस की कार्यप्रणाली की जानकारी अधिकारियों से ली।

बता दें कि 18 मई को डायल 112 की 400 से ज्यादा अत्याधुनिक वाहनों का केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के हाथों शुभारंभ किया गया। यह सेवा 24म7 संचालित होगी। इसमें जीआईएस आधारित मॉनिटरिंग, एडवांस व्हीकल ट्रैकिंग, एसआईपी ट्रंक टेक्नोलॉजी और स्वचालित कॉलर लोकेशन पहचान जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है। राज्य के सभी 33 जिला समन्वय केंद्रों को भी इस नेटवर्क से जोड़ा गया है। नागरिक वॉयस कॉल, एसएमएस, ईमेल, वेब पोर्टल, व्हाट्सएप, चैटबॉट और SOS-112 इंडिया ऐप के माध्यम से भी सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर सियासत

टीएस बाबा को अजय चंद्राकर ने दी कांग्रेस छोड़ने की नसीहत

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर सियासत जारी है। राजनीतिक बयानबाजी के दौर के बीच अब भाजपा विधायक अजय चंद्राकर का बड़ा बयान सामने आया है। चंद्राकर ने दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस। सिंहदेव को कांग्रेस छोड़ने की नसीहत दी है।

दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के मैं टीएस सिंहदेव के बयान पर प्रतिक्रिया नहीं देता वाले बयान को लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद कांग्रेस का एक मिशन बन गया था, कि बाबा साहब को अपमानित करो। बाबा साहब को सलाह दूंगा कि कांग्रेस छोड़ दें। अपमान की एक पराकाष्ठा होती हैं। बाबा साहब एक गौरवशाली वंश से आते हैं। अब बाबा साहब को फैसला करना है कि कांग्रेस में अपमानित होना है या राष्ट्र के विकास के साथ अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाना है।

छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी नक्सली हमले को सोमवार को 13 साल पूरे होने पर अजय चंद्राकर का बयान सामने आया। चंद्राकर कहा कि जिस दिन भूपेश बघेल अपने जेब में रखे सबूत को सार्वजनिक करेंगे। कवासी लखमा को सामने रख पूरे प्रदेश की जनता को घटनाक्रम बतायेंगे। नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने कवासी लखमा को हॉस्पिटल में क्या कहा था? जिस दिन ये सारी बातें सामने आएगी, सारी परते खुद-ब-खुद खुलती जाएगी। आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने केवल सहानुभूति के लिए अपना राजनीतिक ऑक्सीजन बना रखा हैं। भाजपा ने इस मामलें में हर स्तर की कार्रवाई की है।

पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के उस बयान पर भी अजय चंद्राकर ने निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा था कि खनिज संसाधनों से आदिवासियों को हिस्सा मिलना चाहिए। इस पर भाजपा विधायक ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर इतनी चिंता थी तो अपनी सरकार के दौरान विधानसभा या कैबिनेट में यह मुद्दा क्यों नहीं उठाया? क्या केंद्र सरकार को एक भी पत्र लिखा गया?

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सत्ता में रहते समय अपनी बात रखने का साहस नहीं होता, लेकिन कुर्सी जाने के बाद वे राजनीतिक चमकाने के लिए बड़े-बड़े बयान देते हैं।

दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से की मुलाकात सुशासन और शहरी विकास पर हुई बात

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय दिल्ली दौरे पर हैं। अपने व्यस्त दिल्ली दौरे पर सीएम ने आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की। ये मुलाकात वैसे तो सौजन्य मुलाकात रही, लेकिन दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच कई अहम विषयों पर भी चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सीएम रेखा गुप्ता के साथ सुशासन, जनहित और शहरी विकास के मुद्दों पर अहम चर्चा की। दोनों की ये मुलाकात सीएम रेखा गुप्ता के आवास पर हुई। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने अपने-अपने राज्यों में चल रही योजनाओं को लेकर भी चर्चा की। मुलाकात के दौरान जनहित, सुशासन, शहरी विकास और सार्वजनिक सुविधाओं में विस्तार और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय जैसे विषयों पर चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान सीएम विष्णु देव साय ने सीएम रेखा गुप्ता को छत्तीसगढ़ में चल रहे विकास कार्यों की भी जानकारी दी। सीएम साय ने रेखा गुप्ता को बताया कि कैसे हम जनकल्याणकारी योजनाओं के जरिए छत्तीसगढ़ की जनता को लाभ पहुंचा रहे हैं।

मुलाकात के दौरान दोनों मुख्यमंत्रियों ने देश के विकास में अपने-अपने राज्यों की अहम भूमिका और आपसी सहयोग पर भी जोर दिया। दोनों नेताओं के बीच समसायमिक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया है। सीएम विष्णु देव साय ने सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात के दौरान उनको छत्तीसगढ़िया संस्कृति से जुड़ी कई भेंट भी गिफ्ट किए।

बीते दिनों केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बस्तर दौरे पर थे। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ और बस्तर में चल रहे विकास के कार्यों को लेकर साय सरकार की तारीफ की थी। छत्तीसगढ़ और देश से नक्सलवाद के खत्म होने के ऐलान के बाद से छत्तीसगढ़ लगातार विकास योजनाओं पर फोकस करने में लगा है। सीएम कई मंचों से खुद ये कह चुके हैं कि वो बस्तर के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे।

झीरम कांड की 13वीं बरसी पर दीपक बैज बोले-

भाजपा नहीं चाहती घटना की सच्चाई सामने आए

सूरजपुर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सूरजपुर में झीरम हमले की 13वीं बरसी पर भाजपा पर तंज कसा। उन्होंने कहा, भाजपा नहीं चाहती कि झीरम हमले की जांच हो। सरकार लाइव टेलीकास्ट कर नक्सलियों से पूछताछ करें। बैज ने बड़ा आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता घटना में शामिल हैं इसलिए जांच को प्रभावित कर रहे।

दीपक बैज ने कहा, अब तो सभी बड़े नक्सली लीडर आत्मसमर्पण कर चुके हैं। सरकार उनसे क्यों नहीं जानकारी लेकर कार्रवाई कर रही। पूछताछ में हमले का जिम्मेदार कौन है, इसका पता चल जाएगा। बैज ने कहा, पीड़ित परिवार व कांग्रेस परिवार आज भी न्याय की उम्मीद में बैठे हैं। भाजपा जांच प्रभावित कर रही है। एनआईए ने जांच रिपोर्ट कांग्रेस को नहीं दी।

झीरम कांड सबसे बड़ा नक्सली हमला था। यह घटना 25 मई 2013 को घटी थी। उस वक्त कांग्रेस के कई दिग्गज नेता परिवर्तन यात्रा कर रहे थे। इस यात्रा के दौरान उनका काफिला सुकमा से लौट रहा था। जैसे ही उनका काफिला दरभा के झीरम घाटी पहुंचा, वैसे ही घात लगाए बैठे नक्सलियों ने काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। इस घटना में नेताओं, सुरक्षा बलों को मिलाकर 33 लोगों की मौत हो गई थी। आज भी इस कांड को याद करके नेता सिहर उठते हैं।

दिल दहला देने वाले इस कांड को अंजाम देने के लिए 500 से ज्यादा नक्सली तैनात किए गए थे। इन नक्सलियों में 300 हार्डकोर नक्सली थे। ये नक्सली बीजापुर, सुकमा, दरभा और दंतेवाड़ा से बुलाए गए थे। इनती बड़ी संख्या में नक्सलियों की तैनाती का खुफिया तंत्र को अंदाजा भी नहीं था। बताया जाता है कि इस घटना में कई नक्सली भी घायल हुए थे।

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: सुप्रीम कोर्ट से पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास को मिली जमानत

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शराब नीति घोटाले से जुड़े दो मामलों में निरंजन दास को जमानत दी, लेकिन उन्हें प्रदेश से बाहर रहना होगा।

बता दें कि वे पिछले करीब दो वर्षों से जेल में बंद थे। उन पर कथित शराब सिंडिकेट, अवैध कमीशनखोरी और शराब नीति में हेरफेर कर करोड़ों रुपये के घोटाले में भूमिका निभाने के आरोप हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार यह घोटाला कांग्रेस शासनकाल के दौरान वर्ष 2019 से 2022 के बीच हुआ था।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने मुख्य मामले से जुड़े दो अलग-अलग मामलों और संबंधित मनी लांड्रिंग मामले में सुनवाई करते हुए पूर्व आयुक्त को राहत प्रदान की। इससे पहले अनिल टुटेजा और एपी त्रिपाठी को भी जमानत मिल चुकी है। पीठ ने कहा कि निरंजन दास को कथित तौर पर इस मामले का मुख्य सूत्रधार बताया गया है और उन पर आरोप है कि उन्होंने राज्य की आबकारी नीति तैयार करने में भूमिका निभाई ताकि अन्य सह-आरोपियों को लाभ पहुंचाया जा सके।

जमानत देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि दास को दो अलग-अलग मामलों में क्रमशः 18 सितंबर 2025 और 19 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने उन पर वही जमानत शर्तें लागू की है, जो अन्य सह-आरोपियों पर लागू हैं। इसके तहत उन्हें राज्य से बाहर रहना होगा और वह केवल मुकदमे की सुनवाई तथा जांच में शामिल होने के लिए ही छत्तीसगढ़ आ सकेंगे। हालांकि, पीठ ने यह भी कहा कि वह भविष्य में जमानत की शर्तों में ढील देने की मांग कर सकते हैं। इससे पहले एक मार्च को हाईकोर्ट ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) में उप सचिव रहीं सौम्या चौरसिया को भी शराब घोटाले से जुड़े दो मामलों में जमानत दी थी।

बकरीद से पहले छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की मुस्लिम समाज से बड़ी अपील

■ खुले क्षेत्रों में न करें कुरबानी, सभी समाज की आस्था का रखें ध्यान

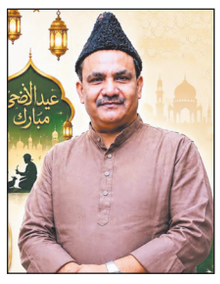

रायपुर। ईद-उल-अज़हा पर्व से पहले छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने मुस्लिम समाज से सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने कहा है कि खुले क्षेत्रों और सार्वजनिक स्थानों पर कुरबानी न करें तथा सभी समाज की धार्मिक भावनाओं और आस्था का विशेष ध्यान रखें।

डॉ. सलीम राज ने बताया कि आगामी 28 मई 2026, गुरुवार को पूरे देश सहित छत्तीसगढ़ में ईद-उल-अज़हा का त्योहार मनाया जाएगा। प्रदेशभर की मस्जिदों और ईदगाहों में सुबह 6 बजे से 11 बजे तक निर्धारित समय के अनुसार ईद की नमाज अदा की जाएगी और लोग एक-दूसरे को मुबारकबाद देंगे।

डॉ. सलीम राज ने कहा कि ईद-उल-अज़हा का त्योहार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद में मनाया जाता है। इस दौरान 28 मई के सूर्योदय से 30 मई के सूर्यास्त तक साहिबे निसाब मुस्लिमों द्वारा कुरबानी की जाती है।

उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म हमेशा अमन, भाईचारे और सभी धर्मों के सम्मान का संदेश देता है। पैगंबर साहब ने भी यह शिक्षा दी है कि जिस देश में हम रहते हैं, वहां के संविधान और समाज की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। कुरआन और हदीस भी मोहब्बत, आपसी सद्भाव और साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की सीख देते हैं।

वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि कई बार कुछ लोग खुले क्षेत्रों में कुरबानी करते हैं या उसके फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं, जिससे अन्य समाज के लोगों की भावनाएं आहत होती हैं और सामाजिक वातावरण प्रभावित होता है। इसे देखते हुए मुस्लिम समाज से विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है।

उन्होंने समाज के लोगों से आग्रह किया कि सार्वजनिक स्थानों पर कुरबानी बिल्कुल न करें, प्रतिबंधित पशुओं की कुरबानी से बचें और कुरबानी से जुड़े फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर साझा न करें। साथ ही कुरबानी के बाद साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने, खून को नालियों में न बहाने और अपशिष्ट पदार्थों को गड्ढा खोदकर दफनाने की भी अपील की गई है। इसके अलावा ईद की नमाज को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं। वक्फ बोर्ड ने कहा है कि सड़क पर नमाज अदा न करें और यदि किसी स्थान पर जमात अधिक हो तो पूर्व वर्षों की तरह अलग-अलग पालियों में नमाज की व्यवस्था की जाए। डॉ. सलीम राज ने कहा कि ईद-उल-अज़हा का त्योहार प्रेम, त्याग और इंसानियत का संदेश देता है। ऐसे में सभी समाजों की आस्था का सम्मान करते हुए शांति, भाईचारे और साम्प्रदायिक सौहार्द के साथ त्योहार मनाना चाहिए।

रामभद्राचार्य को जगदगुरु मानने से महंत ने किया इंकार

■ कहा- वह भाजपा के प्रचारक, धीरेंद्र शास्त्री को बताया फर्जी बाबा

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने रामभद्राचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री समेत धार्मिक गुरुओं को लेकर ऐसा बयान दिया, जिससे प्रदेश का सियासी पारा बढ़ गया है। सोमवार को मनेन्द्रगढ़ दौरे में मीडिया से चर्चा में महंत ने कहा कि वह रामभद्राचार्य को जगद्गुरु नहीं मानते हैं और चिरमिरी में चल रही कथा में नहीं जाएंगे।

चरणदास महंत ने कहा कि रामभद्राचार्य जिस प्रकार से भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, वह सिर्फ भाजपा के प्रचारक है। ऐसे बाबा लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ज्ञान के माध्यम से ठग रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री जैसे सभी बाबा फर्जी हैं। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से ऐसे कार्यक्रमों में नहीं जाने की अपील की। साथ ही कहा कि हम तो कण कण में भगवान मानने वाले लोग हैं। हमारे तो कण-कण में भगवान है।

बंगाल के मुस्लिम बहुल सीटों की बदलती राजनीतिक सोच

सत्येंद्र प्रताप सिंह

फलता विधानसभा सीट का यह नतीजा इसलिए चौंकाने वाला माना जा रहा है, क्योंकि यह सीट डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के भीतर आती है। जिसे 12 वर्ष से अभिषेक बनर्जी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। 2021 विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस यहां करीब 40 हजार वोट से जीती थी, जबकि 2024 लोकसभा चुनाव में इसी क्षेत्र में अभिषेक बनर्जी को करीब एक लाख 68 हजार की भारी बढ़त मिली थी। 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव में फलता विधानसभा सीट पर तस्वीर बदली है। इसके पीछे अनगिनत कारण दिखाई देते हैं। छह मुख्य कारणों पर नजर डालते हैं। इपहला कारण, तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान का चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मैदान से हटना, पार्टी कैडर और वोटरों में भ्रम पैदा कर गया। इससे संदेश गया कि पार्टी अंदरूनी दबाव या संकट में है। दूसरा कारण, बंगाल में कई बार देखा गया है कि लोकसभा और विधानसभा में वोटिंग पैटर्न अलग होता है। अभिषेक बनर्जी की व्यक्तिगत लोकप्रियता लोकसभा में काम आई, लेकिन विधानसभा चुनाव में स्थानीय असंतोष, उम्मीदवार की छवि और संगठन की स्थिति ज्यादा प्रभाव डालती है। तीसरा कारण, डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी खुद पार्टी उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनाव प्रचार में सक्रिय नहीं दिखे। इससे कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह कम हुआ और विरोधी दलों खासकर भाजपा को हमला करने का मौका मिला। चौथा कारण, भाजपा का आक्रामक माइक्रो-कैंपेन। भाजपा ने इस चुनाव को प्रतीकात्मक लड़ाई बना दिया, अभिषेक के गढ़ में सेंध वाली चुनावी रणनीति के साथ। लगातार बूथ स्तर पर काम और ध्रुवीकरण की कोशिशों का असर दिखा। पांचवां कारण, पुनर्मतदान और चुनावी तनाव। फलता समेत इलाके में पुनर्मतदान, शिकायतें और प्रशासनिक विवाद भी चर्चा में रहे। अमूमन ऐसे माहौल में एंटी-इंकम्बेंसी और असंतोष ज्यादा संगठित रूप में सामने आता है। छठा कारण, अत्यधिक आत्मविश्वास का नुकसान। बड़ी लोकसभा बढ़त के बाद तृणमूल कांग्रेस ने शायद इस सीट को सेफ मान लिया। वहीं भाजपा ने इसे प्रतिष्ठा की लड़ाई बनाकर पूरी ताकत झोंक दी। कई चुनावों में यही अंतर परिणाम बदल देता है। कुल मिलाकर, यह सिर्फ एक सीट का परिणाम नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे बंगाल की राजनीति में एक संकेत की तरह देखा जा रहा है कि मजबूत गढ़ों में भी स्थानीय असंतोष, उम्मीदवार चयन और संगठनात्मक कमजोरी भारी पड़ सकती है। बंगाल की मुस्लिम बहुल सीटों की राजनीति में अब स्पष्ट बदलाव दिखाई भी दे रहा है। लंबे समय तक मुस्लिम वोट बैंक को तृणमूल कांग्रेस का एकतरफा समर्थन माना जाता था, लेकिन अब उसमें जबरदस्त विभाजन नजर आने लगा है। बदलाव का ही असर है कि इस बार राज्य की 142 मुस्लिम-बहुल सीटों में भाजपा न केवल अपना खाता खोलने में सफल रही, बल्कि आधे से अधिक यानी 73 सीटों पर जीत दर्ज की। हालांकि, भाजपा की ओर से अब भी एक भी मुस्लिम विधायक निर्वाचित नहीं हुआ है। दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस सिमटकर महज 63 सीटों पर रह गई है। तृणमूल कांग्रेस के कुल 80 विधायकों में 32 मुसलमान हैं। वहीं कांग्रेस, सीपीएम, आईएसएफ (नौशाद सिद्दिकी) और आजउपा (हुमांयू कबीर) के जितने भी विधायक जीतकर आए हैं, वे सभी मुस्लिम समुदाय से हैं। यह बदलता राजनीतिक समीकरण संकेत देता है कि बंगाल में मुस्लिम मतदाता अब पहले की तरह एकजुट होकर किसी एक दल के साथ नहीं खड़े हैं, बल्कि स्थानीय मुद्दों, उम्मीदवारों और राजनीतिक विकल्पों को ध्यान में रखकर मतदान कर रहे हैं।

महंगाई : मोदी सरकार के सामने बड़ी चुनौती

शेखर गुप्ता

इतिहास खुद को दोहराता है, इस पर हम किस की बात मानें, कार्ल मार्क्स की या मार्क ट्वेन की? इस पर मतभेद हो सकता है। मार्क्स ने कहा था कि इतिहास खुद को दोहराता है, पहली बार त्रासदी के रूप में और दूसरी बार प्रहसन के रूप में। ट्वेन ने तर्क दिया कि इतिहास खुद को दोहराता नहीं है मगर अक्सर पहले जैसा लगता है। आजकल की घटनाओं पर नजर डालें तो लगता है कि हम 1973 के ऐतिहासिक संकट की ओर लौट रहे हैं। फिर आप चाहें मार्क्स के शब्द चुनें या ट्वेन के।

मैं मार्क्स के बजाय ट्वेन को चुनूंगा क्योंकि अगर गलती होने का जोखिम हो तो मैं आशावाद के साथ गलती पसंद करूंगा। यदि आज की घटनाएं 1973 से मिलती-जुलती लगती हैं तो संगीत की भाषा में उनकी धुन कोमल, शुभ या रोमानी नहीं होगी। ये भविष्य में विलाप की धुनें हैं, मगर हम इन्हें प्रलयकारी नहीं कहेंगे। इसकी वजह यह है कि भारत पिछले 53 साल में काफी मजबूत हो चुका है।

बात करते हैं 1973 की। इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनावों में एकतरफा जीत हासिल की थी। अपने साझेदारों के साथ उन्होंने 80 फीसदी सीटें जीत ली थीं। साझेदारों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) शामिल थीं। उसी साल उन्होंने पाकिस्तान को पराजित किया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। अगले साल 19 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चुनाव हुए, जिनमें से 15 में उन्होंने जबरदस्त जीत दर्ज की। जिन चार राज्यों ङ्क मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और गोवा में उनकी हार हुई, वे छोटे थे और मिजोरम, गोवा तो केंद्रशासित प्रदेश थे। वह अपनी सत्ता और शोहरत के शिखर पर थीं। पार्टी, कैबिनेट और संसद उनकी मुट्ठी में थे। किसी भारतीय नेता का वैसा जलवा नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी अब उसके करीब हैं और यह बात भी 1973 के जैसी ही है।

उसके बाद हालात नाटकीय ढंग से बदले। पहले 1972-73 में लगातार मॉनसून खराब रहा। ऐसा कम ही होता है कि लगातार मॉनसून खराब हो। इससे पहले 1965-66 में ऐसा हो चुका था। इससे कृषि अर्थव्यवस्था वाले देश में हरित क्रांति के फायदे बेअसर हो गए। 1973 में योम किपुर युद्ध के साथ तेल का झटका लगा जब पहली बार पश्चिम एशिया के इस्लामिक देशों ने तेल को

हथियार बना लिया। तेल की कमी और बढ़ती कीमतों ने सूखे की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। इससे देश के युवाओं में नाराजगी पैदा हुई। इसकी शुरुआत गुजरात से हुई।

वहां नवनिर्माण आंदोलन राजनीतिक नहीं था। बेरोजगारी, किराये और बढ़ती कीमतों से हो रही आर्थिक दिक्कतों ने हर किसी को प्रभावित किया था। वहां कॉलेज छात्रावासों के मेस का शुल्क बढ़ाने से चिंगारी भड़क उठी और फिर मामला गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल के विरुद्ध भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों में बदल गया, जहां 'चिमन चोर' के नारे लगने लगे। जल्द ही बिहार में छात्र कार्यकर्ताओं ने अपनी बिहार छात्र संघर्ष समिति बना ली और महंगाई तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ दमदार जंग छेड़ दी। इनमें लालू प्रसाद और नीतीश कुमार प्रमुख थे। उन्होंने जयप्रकाश नारायण को नेतृत्व के लिए आमंत्रित किया। इंदिरा गांधी चौकन्नी हो गईं और कई तरीके से जवाब दिया। चिमनभाई पटेल को हटा दिया गया। बिहार में अब्दुल गफूर ने 1974 तो किसी तरह गुजार लिया मगर अप्रैल 1975 में उन्हें भी जाना पड़ा। 1974 की गर्मियों में गांधी ने पोखरण परमाणु परीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि विदेशी ताकतें, खास तौर पर सीआईए उनकी सरकार गिराना चाहती हैं। लेकिन जनता का रुख नहीं बदला। बदलता भी कैसे जब बेरोजगारी चरम पर थी और 1974 में महंगाई 29 फीसदी हो गई थी। उसी साल सितंबर में महंगाई 34.68 फीसदी तक जा पहुंची।

तब इंदिरा ने अपनी ही जनता पर एक भीषण हथियार चला दिया। आपातकाल हमारे लोकतंत्र के लिए हमेशा कलंक बना रहेगा और वह भी उन्हें बचा नहीं पाया। निष्पक्ष चुनाव और अपमान भरी हार ही 1977 में उनके लिए गंगा स्नान बनी।

पिछले 18 महीनों की घटनाओं पर नजर डालें और आगे देखें। पश्चिम एशिया के युद्ध के साथ एक नया तेल संकट सामने है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने इतनी भारी निकासी की है कि 20 अरब डॉलर देश से बाहर चले गए। शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) लगभग शून्य है क्योंकि कई बड़ी भारतीय कंपनियां विदेश में निवेश कर रही हैं। रुपये के लिए यह सब भारी पड़ रहा है और विडंबना यह है कि कमजोर होते डॉलर के सामने भी रुपया गिर रहा है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) के अंतिम वर्षों में रुपये की मजबूती को सियासी मुद्दा बनाकर बड़ी गलती कर दी थी। अब यह क्रिकेट के नर्वस नाइंटी जैसा मामला हो गया है मगर कुछ उलटी स्थिति है। क्रिकेट में 90 रन पार करने के बाद बल्लेबाज यह सोचकर घबराता रहता है कि एक-दो रन पहले आउट होकर 100 रन बनाने से चूक न जाए। यहां घबराहट यह सोचकर है कि रुपया 1-2 रुपये और गिरकर डॉलर के मुकाबले 100 पर न पहुंच जाए। आपकी मुद्रा वैश्विक बाजारों और आपकी अर्थव्यवस्था की सेहत के हिसाब से चलेगी। मुद्रा का राष्ट्रवाद बेतुकी बात थी और हमेशा रहेगी। कम से कम चीनियों से हमें यह सीखना चाहिए, जिन्होंने बहुत जल्दी समझ लिया था कि मुद्रा कमजोर रखने में उनका फायदा है।

यह तेल संकट 1973 की याद दिलाता है। सरकार को मूल्य वृद्धि का बोझ उपभोक्ताओं पर ही डालना होगा, महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी और चुभेगी। 1973 की मॉनसून विफलताओं की याद भी चेतावनी देती है कि यह अल नीनो का साल है। हालांकि हमें नहीं पता कि इसका असर क्या होगा। 1973 के मुकाबले अब कृषि हमारे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का बहुत छोटा हिस्सा है लेकिन लोगों पर कृषि संकट से ज्यादा असर कोई और संकट नहीं डालता। यही कारण है कि सबके मिजाज पर नजर रखें, खासकर युवाओं पर।

कुछ संकेत स्पष्ट हैं। नीट विवाद इस गुस्से को दर्शाता है। हमारी सरकार कारोबारी सुगमता की बात करती है, लेकिन उन युवाओं की कठिनाई भी देखिए, जिन्हें गिनी-चुनी नौकरियों या नौकरी दिलाने लायक शिक्षा के लिए होड़ करनी पड़ती है। कैट, नीट, जेईई, क्लैट, यूपीएससी, एनडीए, आईएमए और यहां तक कि अग्निवीर में भर्ती के लिए परीक्षाएं हो रही थीं और अब कॉलेज में दाखिले के लिए सीयूईटी भी है।

इन सबके बीच आज का युवा कोचिंग सेंटर अर्थव्यवस्था के चक्रव्यूह में फंस गया है। मध्य वर्ग की पहले ही बिगड़ी माली हालत को यह और भी बिगाड़ रहा है और निम्न मध्य वर्ग तो कर्ज में धंसता जा रहा है। इतने सब के बाद भी हमें पता चलता है कि कुछ लोग सिस्टम को धोखा दे रहे हैं, परीक्षा रद्द हो रही है और हमें पूरी कवायद एक बार फिर करनी पड़ रही है।

जरा सोचिए कि युवा भारतीय और उनके माता-पिता कितने गुस्से में होंगे? खासकर तब, जब उन्हें सरकार का जवाब मिलता है ङ्क हम धोखेबाजों को जेल में डालेंगे और परीक्षा फिर से कराएंगे। यह कहना कठिन है कि यह गुस्सा उतना ही तगड़ा है, जितना 1973-74 में गुजरात में कॉलेजों की फीस या बिहार में महंगाई पर था। परंतु भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक बिना सोचे कही एक बात पर मजाक के तौर पर शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी जितने बड़े स्तर पर पहुंच गई है, उससे हमें कुछ संकेत मिलते हैं। हफ्ते भर में ही लाखों युवा भारतीय इसके सोशल मीडिया हैंडल्स पर उमड़ पड़े, जिससे घबराई सरकार को इसका एक्स हैंडल बंद कराना पड़ा। जब यह लेख लिखा जा रहा था तब इंस्टाग्राम पर इसके 2.1 करोड़ फॉलोअर थे, जो भारतीय जनता पार्टी के फॉलोअरों से ढाई गुना हैं। हां, प्रधानमंत्री 10.1 करोड़ फॉलोअर के साथ बहुत आगे हैं।

हम कह ही चुके हैं कि यह अलग किस्म का और ज्यादा मजबूत भारत है। महंगाई तो बढ़ेगी ही, वृद्धि धीमी पड़ेगी ही और सरकार की माली हालत पर असर पड़ेगा ही। फिर भी कुछ वृद्धि होगी और होर्मुज स्ट्रेट भी एक न एक दिन खुल ही जाएगा। मोदी सरकार की चुनौती इसलिए भी कम हो जाती है कि आज के विपक्ष और उसके प्रमुख नेता की 1973 के नेताओं जैसी विश्वसनीयता नहीं है।

उनके पास पहले से ही जन आंदोलनों, संसदीय कौशल, ट्रेड यूनियनों और किसानों के आंदोलनों का लंबा रिकॉर्ड था। सबसे बड़ी बात यह थी कि 1960 के दशक के अंत में संयुक्त विधायक दल के क्षणिक दौर को छोड़ दें तो वे सत्ता से लगभग अछूते थे। उन पर यह आरोप नहीं लग सकता था कि सब एक जैसे ही हैं। यही अंतर देखकर हम मार्क्स के बजाय ट्वेन को चुनते हैं। आज का दौर 1973 से मेल खाता है। ऊपर बताई बातें मोदी सरकार को कुछ राहत देती हैं मगर पूरी तरह बख्श नहीं देती हैं। अगर सरकार इस राहत या गुंजाइश का इस्तेमाल समझदारी से नहीं करती है, पारदर्शिता नहीं दिखाती है, वास्तविक सुधार खास तौर पर उच्च शिक्षा में सुधार नहीं करती है तो यह गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

परन्तु अपने दादागुरु के सत्यार्थप्रकाश (पृष्ठ 237) का वह लेख नहीं सूझा कि जिसमें स्वामी जी ने तिब्बत की पहाड़ियों पर युवा युवितियों के जोड़ों का धड़ाधड़ बरस जाना लिखा है। ई हजरत! पुराण में तो भला साकार मूर्तिमान् मनु राजा की नाक से, साकार बच्चे का उत्पन्न हो जाना ही लिखा है जो कि किसी हद्द तक नास्तिक की भो समझ में आ सकता है, परन्तु आपके दादागुरु जी तो अकायमब्रणम् कहे जाने वाले निराकार से ही साकार जोड़ों की टपकन लगाते हुवे नहीं अघाते! कुछ इस मागप्प का भी ध्यान है।

पृत वेन को मथने से पुत्र

पुराणों में वर्णन आता है कि पापिष्ठ राजा वेन के मर जाने पर ऋषियों ने उसकी जांघ को मथ कर उससे निषाद नामक पुत्र उत्पन्न किया और उसकी भुजाओं को मथ कर उससे प्रसिद्ध सम्राट् पृथु और अचि को पैदा किया यह कथा सर्वथा असम्भव है।

पौराणिक स्वरूप

(क) ममन्थुरूरु तरसा तत्रासीद् बाहुको नरः।।
(श्रीमद्भागवत 4114।43)

(ख) बाहुभ्यां मध्यमानाभ्यां मिथुनं समपद्यत ।
(श्रीमद्भागवत 4। 15 ।1)

अर्थात् (क) उसकी जंघा को मथने से नाटे कद का मनुष्य पैदा हुवा। (ख) [श्रीर] भुजाओं को मथने से एक जोड़ा उत्पन्न हुवा।

समाधान

इस आख्यान के प्रसङ्ग में यह जिक्र आता है कि वेन के मर जाने पर ऋषियों ने सोचा कि निस्सन्तान वेन की राजगद्दी का उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए? तब यह रहस्य ध्यान में आया कि -

अमोघवीर्य्या हि नृपा वंशेऽस्मिन्केशवाश्रयाः।
(श्रीमद्भागवत 4 ।14 ।42)

क्रमशः ...

हो. वे. शेषाद्रि

आज तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का साहित्य हर भाषा में प्रचुर मात्रा में निर्माण हो रहा है; पर इस कार्य के प्रारम्भ में जिन कार्यकर्ताओं की प्रमुख भूमिका रही, उनमें श्री होंगसन्द्र वेंकटरमैया शेषाद्रि का नाम शीर्ष पर है।

26 मई, 1926 को बंगलौर में जन्मे शेषाद्रि 1943 में स्वयंसेवक बने। 1946 में मैसूर विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में प्रथम श्रेणी में स्वर्ण पदक पाकर उन्होंने एम.एस-सी. किया और अपना जीवन प्रचारक के नाते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हेतु समर्पित कर दिया।

प्रारम्भ में उनका कार्यक्षेत्र मंगलौर विभाग, फिर कर्नाटक प्रान्त और फिर पूरा दक्षिण भारत रहा। 1986 तक वे दक्षिण में ही सक्रिय रहे। वे श्री यादवराव जोशी से बहुत प्रभावित थे। 1987 से 2000 तक वे संघ के सरकार्यवाह रहे। इस नाते उन्होंने पूरे भारत तथा विश्व के कुछ देशों में भी प्रवास किया।

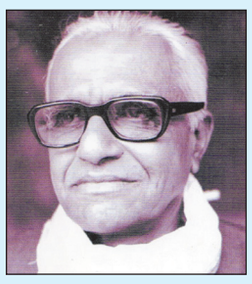

कार्य की व्यस्तता के बाद भी वे प्रतिदिन लिखने के लिए समय निकाल लेते थे। वे दक्षिण के विक्रम साप्ताहिक, उत्थान मासिक, दिल्ली के पांचजन्य और आर्गनाइजर साप्ताहिक तथा लखनऊ के राष्ट्रधर्म मासिक के लिए प्राय: लिखते रहते थे। उनके लेखों की पाठक उत्सुकता से प्रतीक्षा करते थे। उन्होंने संघ तथा अन्य हिन्दू साहित्य के प्रकाशन के लिए श्री यादवराव के निर्देशन में बंगलौर में 'राष्ट्रोत्थान परिषद्' की स्थापना की। सेवा कार्यों के विस्तार एवं संस्कृत के उत्थान के लिए भी उन्होंने सघन कार्य किया।

शेषाद्रि जी ने यों तो सौ से अधिक छोटी-बड़ी पुस्तकें लिखीं; पर उन्होंने ही सर्वप्रथम द्वितीय सरसंघचालक श्री गुरुजी के भाषणों को 'बंच ऑफ थॉट्स% के रूप में संकलित किया। आज भी इसके संस्करण प्रतिवर्ष छपते हैं। इसके अतिरिक्त कृतिरूप संघ दर्शन, युगावतार, और देश बँट गया, नान्य: पन्था, मूल्यांकन, द वे, हिन्दूज अब्रोड डाइलेमा, उजाले की ओर.. आदि उनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। इन सबके कई भाषाओं में अनुवाद हुए हैं। 'तोरबेरलु' को 1982 में कन्नड़ साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया।

शेषाद्रि जी की भाषण शैली भी अद्भुत थी। वे सरल एवं रोचक उदाहरण देकर अपनी बात श्रोताओं के मन में उतार देते थे। 1984 में न्यूयार्क (अमरीका) के विश्व हिन्दू सम्मेलन तथा ब्रेडफोर्ड (ब्रिटेन) के हिन्दू संगम में उन्हें विशेष रूप से आमन्त्रित किया गया था। उनके भाषणों से वहां लोग बहुत प्रभावित हुए।

अत्यधिक शारीरिक एवं मानसिक श्रम के कारण उनका शरीर अनेक रोगों का घर बन गया। जब चैथे सरसंघचालक रज्जू भैया अपने खराब स्वास्थ्य के कारण अवकाश लेना चाहते थे, तो सब कार्यकर्ता चाहते थे कि शेषाद्रि जी यह दायित्व संभालें; पर वे इसके लिए तैयार नहीं हुए। उनका कहना था कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, अत: किसी युवा कार्यकर्ता को यह काम दिया जाये। अन्तत: सह सरकार्यवाह श्री सुदर्शन जी को यह दायित्व दिया गया। शेषाद्रि जी निरहंकार भाव से सह सरकार्यवाह और फिर प्रचारक प्रमुख के नाते कार्य करते रहे। वहीं 14 अगस्त, 2005 की शाम को उनका देहान्त हो गया।

ट्रंप-नेतन्याहू के बीच क्यों हुआ झगड़ा?

अभिनय आकाश

ईरान को घुटनों पर लाने के लिए जिस अमेरिका और इजराइल ने कंधे से कंधा मिलाकर बम बरसाए थे, आज वही दोनों महाशक्तियां आपस में भिड़ गई हैं। वजह कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि वही %ईरान% है जिस पर दोनों मिलकर फतह पाना चाहते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच 19 मई की रात हुई एक सीक्रेट फोन कॉल ने दोनों देशों के रिश्तों में छिपे तनाव को दुनिया के सामने ला दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह बातचीत इतनी तीखी थी कि इसके बाद नेतन्याहू गुस्से से तमतमा उठे थे। अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स सीएनएन और एग्जिओस ने खुफिया सूत्रों के हवाले से इस महा-तनाव की इनसाइड स्टोरी पब्लिश की है। सूत्रों के मुताबिक, करीब एक घंटे चली इस मुश्किल कॉल के बाद नेतन्याहू का पारा सातवें आसमान पर था। अमेरिकी अधिकारियों ने तंज कसते हुए कहा कि कॉल के बाद बीबी (नेतन्याहू) के बालों में आग लग गई थी। नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान के सैन्य ठिकानों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर दोबारा भीषण हमले किए जाएं ताकि वह संभल न सके। वहीं, ट्रंप ने ऐन वक्त पर हमलों को रोक दिया है। वह कतर, सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे खाड़ी मध्यस्थों द्वारा तैयार %लेटर ऑफ इंटेंट% को मौका देना चाहते हैं, जिसके तहत 30 दिनों के लिए युद्ध विराम और बातचीत का रास्ता खुल सके। इस तनातनी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के सामने एक ऐसा बयान दे दिया, जिसने इजराइल की संप्रभुता और नेतन्याहू के ईगो पर गहरी चोट की है। ट्रंप ने कैमरे पर बेबाकी से कह दिया बेंजामिन नेतन्याहू वही करेंगे, जो मैं उनसे चाहूंगा। नेतन्याहू का मानना है कि ट्रंप का यह यू-टर्न ईरान को परमाणु हथियार बनाने और मिसाइलें रीग्रुप करने का समय दे रहा है। फिलहाल, इस %पावर स्ट्रगल% ने यह साफ कर दिया है कि ईरान वॉर के अगले कदम को लेकर वाशिंगटन और तेल अवीव के बीच सबकुछ ठीक नहीं है।

19 मई 2026 की तारीख वाइट हाउस और यरूशलम फोन लाइन से जुड़े। करीब 1 घंटे तक डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की बात हुई। एग्जिओस की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू इस कॉल के दौरान परेशान नजर आए। बहुत हद तक इसका कारण है 17 मई का दिन। इस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को भरोसा दिलाया था कि अमेरिका मंगलवार यानी 19 मई को ईरान पर नए और घातक हमलों की शुरुआत करेगा। इजराइल इसी की उम्मीद में बैठा था। लेकिन 24 घंटे के भीतर ट्रंप ने यू टर्न ले लिया क्योंकि कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी ने ऐसे हमले ना करने का अनुरोध किया था। ऐसे में नेतयाहू ने कहा कि हमलों को टालना एक बहुत बड़ी गलती है और इससे केवल ईरान को अपनी सैन्य ताकत फिर से संगठित करने का समय मिलेगा। एग्जिओस ने एक अमेरिकी सूत्र के हवाले से दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत की जानकारी छापी है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि मीडिएटर एक लेटर ऑफ इंटेंट पर काम कर रहे हैं जिस पर अमेरिका और ईरान दोनों साइन करेंगे। जिसका मकसद युद्ध को औपचारिक रूप से खत्म करना है। साथ ही इसके जरिए ईरान के एटम प्रोग्राम और स्टेट ऑफ फोरमच को खोलने जैसे मुद्दों पर 30 दिनों की बातचीत शुरू होगी।

दो इजराइली सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि दोनों नेता ईरान को लेकर आगे के प्लान पर एकमत नहीं हैं। सोर्सेस का कहना है कि वाशिंगटन में इजराइल के राजदूत ने अमेरिकी सांसदों को जानकारी दी थी कि नेतन्या इस बातचीत को लेकर चिंतित थे। हालांकि दूतावास के एक प्रवक्ता ने एक्सियोस को इस बात से इंकार किया और कहा राजदूत निजी बातचीत पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। दरअसल अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर दोबारा हमला करने का प्लान बनाया था। इस बार होने वाले ऑपरेशन को नया नाम दिया गया था। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देश ईरान के खिलाफ ऑपरेशन स्लेज़ हैमर शुरू करने वाले थे। इसी प्लानिंग की वजह से नेतयाओं को लग रहा था कि वह अपना एकमेव लक्ष्य हासिल कर लेंगे। यानी ईरान को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ना आए तो किरदार का नाम ट्रंप का आएगा। ट्रंप ने ऐन वक्त पर ऑपरेशन स्लेज़ हैमर को टाल दिया। ट्रंप ने 18 मई को सोशल मीडिया पर लिखा कि वो ईरान पर 1 घंटे में ही हमला कर सकते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे और डिप्लोमेसी के लिए वक्त देंगे। बस यह ट्विस्ट नेऊ के लिए टेंशन बन गया। क्योंकि जिन ट्रंप के बारे में कहा जाता था कि ईरान पर हुए हमले में इजराइल ने जैसा चाहा अमेरिका ने वैसा ही बिहेव किया। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत अंतिम चरण में है, जबकि तेहरान ने पाकिस्तान के जरिए मिले नए अमेरिकी प्रस्ताव की समीक्षा शुरू कर दी है। ईरान ने अपनी शर्तों में विदेशों में फसी संपत्तियों की रिहाई और ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी खत्म करने की मांग दोहराई है।

ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने निर्देश दिया है कि देश का हथियार-ग्रेड समृद्ध यूरेनियम किसी भी हालत में विदेश नहीं भेजा जाएगा। दो वरिष्ठ ईरानी सूत्रों के हवाले से यह दावा सामने आया है। इस रुख से अमेरिका-ईरान के बीच चल - रही शांति वार्ता में नया पेंच फंस सकता है। इसकी वजह अमेरिका-इजराइल की प्रमुख मांगों में ईरान के यूरेनियम को दूसरे देश में भेजना शामिल है।

अमेरिकी खुफिया आकलन के मुताबिक ईरान सैन्य क्षमता तेजी से खड़ी कर रहा है। युद्धविराम के दौरान उसने ड्रोन प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है। - अनुमान है कि वह 6 महीने में ड्रोन हमले की - क्षमता बहाल कर लेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि -ईरान नष्ट हुई मिसाइल साइट्स, लॉन्चर्स व हथियार उत्पादन क्षमता को भी जल्द तैयार कर लेगा। अमेरिका ने अपना रवैया बदल दिया है। नेतन्याहू के गुस्से की एक बड़ी वजह यह भी थी कि इजराइली खुफिया एजेंसी मोसाद और सैन्य अधिकारियों का मानना है कि ईरान युद्ध के दौरान बंद किए गए अपने मिसाइल ठिकानों को फिर से सक्रिय कर चुका है। इजराइल का मानना है कि इस वक्त ईरान पर हमला ना करना उसे परमाणु बम बनाने की खुली छूट देने जैसा है। उधर ट्रंप और नेतन्या की बातचीत को लेकर मचे बवाल के बीच ईरान का भी जवाब आ गया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने एक्स पर लिखा ईरान ने हमेशा अपने वादे को निभाया है। युद्ध को टालने की हर संभव कोशिश की है। हमारी ओर से रास्ते खुले हैं लेकिन दबाव डालकर ईरान को सरेंडर के लिए मजबूर करना सिर्फ एक भ्रम है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स आईआरजीसी ने और भी सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा अगर अमेरिका ने फिर से हमला किया तो वे खाड़ी देशों के तेल की आपूर्ति को सालों के लिए काट देंगे। धमकी यह भी दी कि अगला हमला किसी क्षेत्रीय संघर्ष तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि यह पूरी दुनिया में फैल जाएगा। तो ट्रंप बातचीत की राह पर हैं। उनके पार्टनर नेतन्या इस बात से निराश हैं। इन दोनों के बीच टेंशन का यह कोई पहला मौका नहीं है। याद कीजिए जंग के दौरान ईरान के साउथ पार्ट्स गैस क्षेत्र पर एक बड़ा हमला हुआ। रिपोर्ट्स आई कि यह हमला इजराइल ने किया। ट्रंप इस हमले की वजह से इजराइल पर भड़क गए तब ट्रंप ने कहा था कि इजराइल ने अकेले कारवाई की है और वाशिंगटन को इस बारे में पहले से कुछ नहीं पता था। ट्रंप ने यह भी कहा था हमने ईरान के साउथ पार्ट्स गैस क्षेत्र इजराइल के हमले का विरोध किया और बेंजामिन नेतन्या से सीधे तौर पर ऐसा ना करने का आग्रह किया था। इसके अलावा ट्रंप ने चेतावनी भी दी थी कि हम ऐसे कामों के लिए मना करते हैं वो नहीं मानते और हमें काम पसंद नहीं आता तो हम आगे काम नहीं करते हैं।

आज का इतिहास

1822 नॉर्वे के इतिहास में सबसे घातक आग नॉर्वे के एक चुरचिन ग्र्यू में हुई, जिसमें कम से कम 113 मौतें हुईं।

1828 कस्पर हॉसर, जो कि संदिग्ध संबंधों के साथ एक संस्थापक है, जो रॉयल हाउस ऑफ बैडेन है, पहली बार जर्मनी के नूर्नबर्ग की गलियों में दिखाई दिया।

1828 माना जाता है कि जंगली बच्चा कास्पर हॉसर नूरमबर्ग, जर्मनी में खोजा गया।

1857 अमेरिकी दास ड्रेड स्कॉट , जो पहले अपनी स्वतंत्रता के लिए मुकदमा कर चुके थे, को उनके मूल मालिक हेनरी टेलरब्लो द्वारा मुक्ति मिली थी।

1865 अमेरिकी सिविल वॉर-जनरल एडमंड किर्बी स्मिथ ने अपनी सेना के समर्पण पर बातचीत की, युद्ध में एकमात्र महत्वपूर्ण कॉन्फेडरेट आर्मी फॉरेस्मेनिसिंग।

1896 पहली अमेरिकी अंत: मेनहट्टन बीच पर साइकिल दौड़ का आयोजन किया गया।

1897 ड्रेकुला, आयरिश लेखक ब्रैम स्टोकर का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास, वाफर्स्ट प्रकाशित हुआ।

1906 लंदन में वॉक्सहॉल ब्रिज खोला, टेम्सबेटिवेन वॉक्सहॉल और वेस्टमिंस्टर नदी को पार करते हुए।

1908 लंदन में फ्रेंको-ब्रिटिश प्रदर्शनी का आयोजन हुआ।

1926 लेबनान में संविधान को अंगीकार किया गया।

1938 हाउस अन-अमेरिकन एक्टिविटी कमेटी की स्थापना कम्युनिस्ट या फासीवादी संबंधों के संदेह वाले लोगों की असंगठितियों द्वारा कथित असमानता और विध्वंसक गतिविधियों को रोकने के लिए की गई थी।

1940 द्वितीय विश्व युद्ध-छोटे जहाजों के एक फ्लोटिला ने डनकिर्क की लड़ाई के दौरान जर्मन सेना द्वारा ब्रिटिश, फ्रांसीसी और बेल्जियम के सैनिकों का एक युद्धपोत शुरू किया।

1950 ब्रिटेन में पेट्रोल खरीदने पर लगी सीमा को खत्म कर दिया गया। इससे पहले हर व्यक्ति को पेट्रोल खरीदने के लिए राशन कार्ड दिया जाता था।

1955 चार्ल्स इवान्स ने दुनिया की तीसरे नम्बर की सबसे ऊँची पर्वत चोटी कंचनजंघा पर विजय प्राप्त की थी, जिसकी ऊँचाई 8585 मीटर है।

1966 ब्रिटिश गुयाना ने स्वतंत्रता प्राप्त की और गुयाना बन गया। ब्रिटिश गुयाना दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर ब्रिटिश उपनिवेश का नाम था, जिसे 1966 में गुयाना के स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। इसके स्वदेशी लोग अरवाक भाषी लुसयान हैं, जो तेनो लोगों का हिस्सा हैं।

स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट क्या है? यह सीमा रक्षा के लिए क्यों जरूरी है?

कमलेश पांडे

स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट भारत की सीमाओं को पारंपरिक तारबंदी और मानव गश्त से आगे बढ़ाकर तकनीक आधारित इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा कवच में बदलने की योजना है। इसे मुख्यत: कम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के तहत विकसित किया गया है। हाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर बड़े स्तर पर स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट लागू किया है।

स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सीमा पर केवल बाड़ नहीं होती, बल्कि एआई आधारित निगरानी, सेंसर नेटवर्क, ड्रोन और रडार, थर्मल कैमरे, भूमिगत सेंसर, सैटेलाइट और फाइबर नेटवर्क, रियल टाइम कमांड सेंटर आदि सभी को परस्पर जोड़कर इंटेलिजेंट बॉर्डर बनाया जाता है।

सवाल है कि आखिर स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट में कौन-कौन सी तकनीकें अनुप्रयुक्त होती हैं? तो यह जान लीजिए कि स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट में नअनुप्रयुक्त तकनीकें निम्नलिखित हैं :- पहला, थर्मल इमेजर और नाइट विजन का उपयोग किया जाता है जो रात, कोहरा, बारिश या धूलभरी आंधी में भी गतिविधि पकड़ लेते हैं। दूसरा, लेजर और इन्फ्रारेड अलार्म का उपयोग किया जाता है जिससे कोई व्यक्ति सीमा पार करे तो तुरंत अलर्ट मिलता है। तीसरा, ग्राउंड सेंसर की खासियत यह है कि ये भूमिगत सुरंग या कंपन तक पहचान सकते हैं। चौथा, ड्रोन और एरोस्टेट के अनुप्रयोग से ऊपर से लगातार निगरानी होती रहती है और बड़े क्षेत्रों में तेजी से ट्रैकिंग सम्भव हो पाता है। पांचवां, रडार और सोनार के उपयोग से नदी या दलदली क्षेत्रों में नावों और गतिविधियों पर निगरानी सम्भव हो जाती है। छठा, कमांड और कंट्रोल सेंटर से सभी सेंसरों की जानकारी एक ही कंट्रोल रूम में पहुंचती है, जहाँ बीएसएफ/आटीबीपी तुरंत प्रतिक्रिया दे सकते हैं।

सवाल है कि आखिर भारत को इसकी जरूरत क्यों है? तो यह जान लीजिए कि निम्नलिखित वजहों से भारत को इसकी जरूरत है :- पहला, आतंकवाद और घुसपैठ रोकने के लिए क्योंकि विशेषकर पाकिस्तान सीमा पर आतंकियों की घुसपैठ बड़ी चुनौती रही है। दूसरा, अवैध प्रवासन रोकने के लिए, क्योंकि बांग्लादेश सीमा पर अवैध घुसपैठ, मानव तस्करी और तस्करी लंबे समय से समस्या रही है। तीसरा, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भारत को इसकी सख्त

जरूरत है, क्योंकि भारत की सीमाएँ- रेगिस्तान, पहाड़, घने जंगल, नदी क्षेत्र, दलदली इलाके से होकर गुजरती हैं, जहाँ सामान्य फेंसिंग कारगर नहीं होती। चतुर्थ,जवानों की सुरक्षा के दृष्टिगत, क्योंकि लगातार गश्त में सैनिकों की जान का जोखिम रहता है। स्मार्ट निगरानी से यह दबाव कम होगा। पांचवां, निरंतर 24म7 निगरानी हेतु, क्योंकि मानव गश्त सीमित होती है, लेकिन सेंसर और एआई चौबीसों घंटे काम कर सकते हैं।

सवाल है कि भारत की किन किन सीमाओं पर यह सबसे ज्यादा जरूरी है? तो यह जान लीजिए कि पहला, पाकिस्तान सीमा पर क्यों जरूरी है? यहां पर आतंकवादी घुसपैठ, ड्रोन से हथियार/नशा भेजना, सीमा पार फायरिंग, सुरंगों का उपयोग किया जाता है। सवाल है कि कहाँ कहाँ विशेष जरूरत है? तो यह समझ लीजिए कि जम्मू सेक्टर, पंजाब सीमा, राजस्थान का रेगिस्तानी क्षेत्र में इसकी सख्त जरूरत है। यही वजह है कि 2018 में जम्मू क्षेत्र में भारत का पहला स्मार्ट फेंस पायलट शुरू किया गया था।

दूसरा, बांग्लादेश सीमा पर क्यों जरूरी है? तो यह समझ लीजिए कि अवैध घुसपैठ, मानव तस्करी, पशु तस्करी, नदी क्षेत्रों से प्रवेश रोकने हेतु इसकी जरूरत है। यहां से जुड़े सबसे संवेदनशील क्षेत्र में असम का धुबरी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल सीमा, त्रिपुरा और मेघालय प्रमुख हैं, जहां की नदी और दलदली इलाकों में प्रोजेक्ट बोल्ड किट लागू किया गया।

तीसरा, चीन सीमा पर क्यों जरूरी? बताया जाता है कि एलएसी पर तनाव, कठिन हिमालयी इलाके, अचानक सैनिक गतिविधियाँ, मौसम संबंधी चुनौतियाँ के दृष्टिगत इसकी जरूरत समझी जाती है। जहां तक कहाँ जरूरत? जैसे सवाल की बात है तो लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के समीप एआई, ड्रोन, सैटेलाइट और हाई-एल्टीट्यूड सेंसर सबसे महत्वपूर्ण होंगे।

चौथा, आखिर म्यांमार सीमा पर क्यों जरूरी है? तो बताया जाता है कि उग्रवाद, हथियार और ड्रग्स तस्करी, अवैध आवाजाही के चलते भारत ने म्यांमार सीमा पर भी स्मार्ट फेंसिंग की दिशा में कदम बढ़ाए हैं।

जहां तक स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट के बड़े फायदे की बात है तो इसके सामरिक फायदे हैं- घुसपैठ में कमी, आतंकवाद पर नियंत्रण और तेज प्रतिक्रिया क्षमता। वहीं आर्थिक फायदे के तौर पर लंबी अवधि में गश्त की लागत कम होगी, तस्करी से होने वाले नुकसान में कमी आएगी। वहीं सामाजिक फायदे के तौर पर सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा भावना, जनसंख्या असंतुलन संबंधी चिंताओं पर नियंत्रण होगा। जबकि तकनीकी फायदे के रूप में मेक इन इंडिया रक्षा तकनीक को बढ़ावा मिलेगा तथा एआई और ड्रोन उद्योग का विकास होगा।

जहां तक चुनौतियों की बात है तो निम्नलिखित चुनौतियाँ इस राह में हैं? पहला, बहुत अधिक लागत- पूरी सीमा पर हाई-टेक सिस्टम लगाना बेहद महंगा है। दूसरा, कठिन मौसम: हिमालय, रेगिस्तान और बाढ़ वाले क्षेत्रों में तकनीक टिकाऊ बनाना चुनौती है। तीसरा, साइबर सुरक्षा- यदि सिस्टम हैक हुआ तो सुरक्षा खतरा बढ़ सकता है। चौथा, स्थानीय सहयोग: सीमावर्ती गाँवों का सहयोग जरूरी है।

सवाल है कि इसे अपनाकर भविष्य में भारत क्या कर सकता है? तो यह जान लीजिए कि एआई आधारित "Predictive Border Security", स्वचालित ड्रोन पेट्रोलिंग, सैटेलाइट आधारित लाइव मॉनिटरिंग, रोबोटिक बॉर्डर पोस्ट और Integrated Defence Grid को अपनाकर भारत अपनी सीमा को और अधिक सुरक्षित बना सकता है।

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट केवल फेंसिंग नहीं बल्कि भारत की सीमा सुरक्षा सोच में बड़ा बदलाव है। यह पारंपरिक चौकियों से आगे बढ़कर डेटा,ड्रोन, सेंसर और रियल टाइम निगरानी आधारित सुरक्षा मॉडल की ओर कदम है। पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर इसकी तत्काल आवश्यकता है, जबकि चीन और म्यांमार सीमा पर यह भविष्य की सामरिक जरूरत बनता जा रहा है। यदि सही तरीके से लागू हुआ, तो यह भारत की सीमा सुरक्षा को 21वीं सदी के स्तर पर ले जा सकता है।

निकोबार में सही पहल, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत के दबदबे को और बढ़ाएगा सामरिक केंद्र

पवन

भारत की उत्तर-पूर्वी सीमाओं पर जिस प्रकार हिमालय प्रहरी है, उसी प्रकार दक्षिणी हिंद महासागर के बंगाल की खाड़ी में अंडमान-कार निकोबार द्वीप समूह स्थित है। भारत की मुख्य भूमि से 1,200-1,400 किलोमीटर दूर 36 द्वीपों के इस समूह में से 30 पर आबादी है। यह द्वीप समूह दक्षिण चीन महासागर और हिंद महासागर के मुहाने पर स्थित है। कार-निकोबार मलक्का जलडमरूमध्य से केवल 160 किलोमीटर दूरी पर है, इसलिए मलक्का से गुजरने वाले सारे जहाजों पर यहां से नजर रखी जाती है। इस तरह कार-निकोबार द्वीप का भी सामरिक महत्व होर्मुज जलडमरूमध्य के समान ही है।

इसी महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने अंडमान और कार-निकोबार द्वीप समूह को समुद्री सुरक्षा और भारत व्यापार के लिए आने जाने वाले जहाजों के लिए विकसित करने की खातिर 10 अरब डॉलर का महत्वाकांक्षी ग्रेट-निकोबार प्रोजेक्ट 2001 में शुरू किया था। इसे हिंद व प्रशांत महासागर क्षेत्र में गेमचेंजर के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि मलक्का के आसपास स्थित देशों का आयात-निर्यात इसी रास्ते से होता है। खासकर, चीन का 80 फीसदी तेल व गैस आयात अरब देशों से होर्मुज होते हुए मलक्का से ही गुजरता है। इस समय भारत के मालवाहक जहाजों को सिंगापुर और कोलंबो इत्यादि में कार्गो ट्रांसमिटमेंट करनी पड़ती है, पर निकोबार में सारी सुविधाएं विकसित होने के बाद भारतीय जहाजों को विदेशी बंदरगाहों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सामरिक दृष्टि से निकोबार में एक मजबूत सैनिक ठिकाना एक अच्छा कदम है।

इससे भारत इस क्षेत्र से गुजरने वाले समुद्री यातायात की पूरी निगरानी और अपने मालवाहक जहाजों की सुरक्षा कर सकता है। चीन पूरे हिंद महासागर में अपना नियंत्रण स्थापित करना चाह रहा है। भारत ने भी अपने समुद्री

यातायात को सुरक्षित करने के लिए नेकलेस ऑफ डायमंड नाम की नीति के तहत इंडोनेशिया के सबंग और सिंगापुर में झांकी बंदरगाहों में अपने ठिकाने स्थापित कर लिए हैं। हिंद महासागर में चीन की गतिविधियों पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर सैनिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पर्याप्त सैन्य व्यवस्था नहीं थी। इसलिए, अंडमान-निकोबार द्वीपों की सामरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यहां पर एक अक्तूबर, 2001 को सैनिक कमांड की स्थापना की गई। इस कमांड में तीनों सेनाओं की टुकड़ियां और कोस्ट गार्ड शामिल हैं। इसे थिएटर कमांड के नाम से जाना जाता है। इससे दुश्मन की चुनौती से निपटने के लिए एक कमांडर के नियंत्रण में हर प्रकार की सैन्य सहायता तुरंत उपलब्ध होती है।

निकोबार के सामरिक महत्व के कारण यहां एक अग्रिम निगरानी केंद्र की भी स्थापना की गई है, ताकि समुद्र की ऊपरी सतह के साथ सतह के नीचे की भी निगरानी की जा सके। चीनी आक्रामकता को जवाब देने के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत ने मिलकर क्वाड नामक संगठन बनाया है। अंडमान-निकोबार द्वीप मलक्का जलडमरूमध्य के नजदीक होने के कारण यह इस संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण सामरिक स्थल बन गया है। ग्रेट निकोबार द्वीप के विकास से हिंद महासागर में भारत का दबदबा बढ़ रहा है।

संकट को अवसर में बदल सकता है भारत

अभिजीत मुखोपाध्याय

होर्मुज जलडमरूमध्य में गतिरोध का भारी असर वैश्विक अर्थव्यवस्था झेल रही है। इसका असर सबसे अधिक तेल और ऊर्जा क्षेत्र में महसूस किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कम ईंधन उपयोग करने, कम सोना खरीदने, विदेशी यात्राएं टालने और संभव हो, तो घर से काम करने जैसी सलाह दी थी। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए ये सुझाव विवेकपूर्ण हैं। हालांकि इन सुझावों ने अनिश्चितता का वातावरण भी पैदा कर दिया। भारत इस परिस्थिति को संभाल सकता है और अच्छी बात यह है कि उसके पास पहले से कई नीतिगत साधन मौजूद हैं, जो विकास की गति बनाये रखते हुए इस झटके को कम कर सकते हैं।

सही तरीका घबराना नहीं, बल्कि ऊर्जा प्रबंधन, लक्षित राहत, सप्लाई-साइड उपायों और विश्वसनीय व्यापक आर्थिक संकेतों का संतुलित मिश्रण अपनाना है। भारत पहले भी बाहरी झटकों का सामना कर चुका है और वर्तमान नीतिगत ढांचा पहले की तुलना में अधिक सक्षम है, जो अस्थिरता को संभालते हुए परिवारों और व्यवसायों की रक्षा कर सकता है। तत्काल समस्या एक पारंपरिक आयातित लागत झटका है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, कठिन शिपिंग परिस्थितियां और घरेलू ईंधन मूल्यों में वृद्धि परिवहन, लॉजिस्टिक्स और अंतत: खुदरा महंगाई पर असर डालती हैं।

सकारात्मक पक्ष यह है कि भारत कमजोर आर्थिक आधार पर खड़ा नहीं है। हाल की सरकारी परियोजनाओं और नीतिगत बयानों में मजबूत विकास, राजकोषीय संतुलन और सप्लाई-साइड परिस्थितियों में सुधार पर जोर दिया गया है, जबकि रिजर्व बैंक ने बदलती परिस्थितियों के अनुसार हाल ही में महंगाई और विकास के अनुमानों में संशोधन किया है यानी प्राथमिक नीतिगत लक्ष्य संकट को नियंत्रित करना है, बचाव अभियान चलाना नहीं। पहली प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि अस्थायी लागत झटका व्यापक महंगाई के चक्र में

न बदल जाए। सरकार यह काम ईंधन मूल्य समायोजन को व्यवस्थित रखते हुए, अचानक मूल्य वृद्धि से बचते हुए तथा यथासंभव तेल विपणन प्रणाली का उपयोग कर अस्थिरता को नियंत्रित करके कर सकती है।

दूसरा कदम सबसे कमजोर परिवारों की सुरक्षा का होना चाहिए, न कि कीमतों को अंधाधुंध नियंत्रित करने का प्रयास। मध्यम अवधि में महंगाई को नियंत्रित करने का सबसे मजबूत उपाय सप्लाई-साइड विस्तार है। सरकार संवेदनशील और आवश्यक खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति और खरीद प्रबंधन को तेज कर सकती है, बफर स्टॉक संचालन में सुधार कर सकती है और आंतरिक लॉजिस्टिक्स को सुचारु रख सकती है, ताकि खाद्य महंगाई ईंधन झटके को और न बढ़ाए। परिवहन और वितरण में रुकावटों को कम करना भी जरूरी है। यदि माल ढुलाई लागत तेजी से बढ़ती है, तो इसका असर जल्द ही ईंधन से खाद्य पदार्थों, विनिर्मित वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच जाता है। बेहतर लॉजिस्टिक्स समन्वय, राजमार्गों पर सुचारु आवागमन और आवश्यक वस्तुओं की समय पर आपूर्ति इस प्रभाव को कम कर सकती है। ऊर्जा सुरक्षा ही इस समस्या का मूल रणनीतिक समाधान है।

भारत पहले ही कच्चे तेल की खरीद में विविधता ला चुका है। इस विविधता को और बढ़ाया जाना चाहिए। रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार भी महत्वपूर्ण हैं। भारत ने भंडारण क्षमता विकसित की है और इसके विस्तार की संभावनाओं का आकलन जारी रखा है। साथ ही, मांग प्रबंधन को ऊर्जा नीति का स्पष्ट हिस्सा बनाया जाना चाहिए। ऊर्जा दक्षता मानक, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, औद्योगिक ऊर्जा ऑडिट और मांग-पक्ष प्रबंधन आयातित तेल झटकों के प्रति अर्थव्यवस्था की संवेदनशीलता को कम कर सकते हैं। यह इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह संकट केवल कीमतों से जुड़ा नहीं है, लचीलापन भी इसका हिस्सा है। अर्थव्यवस्था जितनी कम तेल-निर्भर होगी, बाहरी झटकों का प्रभाव उतना ही कम होगा। वृहद आर्थिक स्तर पर, रिजर्व बैंक और सरकार को सतर्क रहना चाहिए। यदि संकट मुख्य रूप से सप्लाई-साइड आधारित रहता है, तो मौद्रिक नीति को अनावश्यक रूप से विकास को बाधित करने से बचना चाहिए।

साथ ही महंगाई की अपेक्षाओं को भी नियंत्रित रखना चाहिए। रिजर्व बैंक की टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि महंगाई का मूल परिदृश्य संभालने योग्य है, पर वैश्विक तेल कीमतों व भू-राजनीतिक जोखिमों पर निगरानी जरूरी है। राजकोषीय नीति को अनुशासित, पर लचीला बनाए रखना चाहिए। सरकार लगातार राजकोषीय संतुलन की दिशा में आगे बढ़ रही है, और यह विश्वसनीयता कठिन समय में एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। सही राजकोषीय दृष्टिकोण यह होगा कि लक्षित हस्तक्षेपों के लिए पर्याप्त गुंजाइश बची रहे। इसका अर्थ है पूंजीगत व्यय की रक्षा करना, क्योंकि यह रोजगार और उत्पादकता को बढ़ावा देता है, जबकि आवश्यकता पड़ने पर सावधानीपूर्वक तैयार अस्थायी उपायों का उपयोग किया जाये। भारत को इस समय को व्यापार और सप्लाई चेन विविधीकरण को तेज करने के अवसर के रूप में भी देखना चाहिए। निर्यात की मजबूती तब बढ़ती है, जब कंपनियां सीमित मार्गों पर निर्भर न रहकर विभिन्न बाजारों और उत्पादन नेटवर्क से जुड़ती हैं। वैकल्पिक व्यापार मार्गों को मजबूत करना, साझेदारियां गहरी करना और मजबूत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क विकसित करना किसी एक भू-राजनीतिक बाधा पर निर्भरता को कम कर सकता है।

जन अपेक्षाओं पर खरे उतरने की एक मुख्यमंत्री की सकारात्मक पहल

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

समूचा उत्तरी भारत भीषण गर्मी की चपेट में चल रहा है तो दूसरी और ना तो राजस्थान में कोई आसन्न विधानसभा या लोकसभा के चुनाव है और ना ही कोई ऐसी आपात् स्थिति जिसमें जनता से सीधा संवाद कायम करना आवश्यक हो, ऐसी स्थिति में ही एक संवेदनशील मुख्यमंत्री के नाते राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गावों में चौपाल आयोजित कर सीधे ग्रामीणों से रुबरु हो रहे हैं, यह वास्तव में जननेता की पहचान व उसकी आमजन के प्रति सोच का परिणाम है। 40 डिग्री से अधिक के तापमान में मुख्यमंत्री की रात्रि चौपाल और फिर रात्रि विश्राम आज के सुविधाभोगी युग में लगभग असंभव लग रहा है पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस लपलपाती गर्मी में गांवों में रात्रि चौपालों के माध्यम से ग्रामीणों से संवाद कायम कर रहे हैं। 5 मई से 16 मई तक राजधानी जयपुर ही नहीं अपितु दूरदराज के इलाकों के गांवों में पांच चौपाल आयोजित कर ग्रामीणों से सीधा संवाद कायम करने के साथ ही रात को उसी गांव के सरकारी स्कूल में रात्रि विश्राम और फिर सुबह गांव में ही प्रात:कालीन भ्रमण के माध्यम से गांववासियों से आत्मीय संवाद कायम कर रहे हैं।

मई माह में मुख्यमंत्री 5 से 16 मई के दौरान प्रतापगढ़ के बम्बोरी, सीकर के जाजोर, अजमेर के पुष्कर के पास कड़ेल, जालौर के पंसेरी और जयपुर के ठिकरिया में ग्राम विकास चौपाल में ग्रामीणों के बीच बैठकर उनसे रुबरु हो चुके हैं। 20 मई को बांसवाड़ा के चुड़ावा और 21 मई को धुम्बाला को ग्रामीण चौपाल और गांव की सरकारी स्कूल में रात्रि विश्राम कर रहे हैं। यह गांव कोई राजधानी जयपुर के पास के नहीं है अपितु प्रदेश के दूरदराज के गांव है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समय निकाल कर इन गांवों में रात्रि चौपाल में ग्रामवासियों की परिवेदनाओं को सुनते हैं, यथा सभव मौके पर ही समाधान करने का प्रयास करते हैं और रात्रि को भोजन भी गांव के ही किसी ग्रामवासी के घर बिना किसी तामझाम के करते हुए देखा जा सकता है। इसके साथ ही खासबात यह है कि इस भीषण गर्मी के दौर में गांव के स्कूल में ही रात्रि को विश्राम करने के साथ ही प्रात:कालीन भ्रमण के दौरान गांववासियों से अपनत्व के साथ मेलमिलाप कर रहे हैं। यह धरातलीय हालातों को समझने, लोगों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं की जानकारी लेने, स्थानीय समस्याओं को समझने और उनके निराकरण का बेहतरीन माध्यम होने के

साथ ही मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर ग्रामवासियों में जिस तरह का संदेश जाता हे उसे हम भलीभांति समझ सकते हैं। क्योंकि आज के हालातों में मुख्यमंत्री तो दूर की बात जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से मिलना भी इतना आसान नहीं होता। फिर सबसे बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री मतलब सरकार आपके बीच आती है तो फिर उसके परिणाम निश्चित रुप से सकारात्मक होते हैं और धरातलीय हालातों को समझने का बेहतर अवसर आसानी से मिल जाता है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की यह पहल सीधा ग्रामीणों से रुबरु होने का सशक्त माध्यम बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ही माने तो इससे गांवों की समस्याओं से रुबरु होने का अवसर मिलता है तो आवश्यक निर्देश मौके पर ही जारी होने से समस्याओं का समाधान भी मौके पर ही हो पाता है। इसके माध्यम से सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के साथ ही स्थानीय समस्याओं यथा पानी, बिजली, स्कूल, स्वास्थ्य, सड़क और इसी तरह की सुविधाओं के धरातल पर हालात को समझने का अवसर मिल जाता है। मौके पर ही समस्याओं के समाधान को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि सीकर के जाजोद गांव में ग्रामीण चौपाल के दौरान छात्राओं की मांग पर एक रात में विद्यालय में विज्ञान संकाय खोलने के आदेश जारी हो गए। यही नहीं अजमेर के कड़ेल गांव में ग्रामीणों से चर्चा के दौरान सामने आया तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नयन के आदेश मुख्यमंत्री के निर्देश पर तत्काल जारी हो गए। यह तो उदाहरण मात्र है पर इससे साफ संदेश जाता है कि ग्रामीण विकास चौपाल कोई दिखावा या औपचारिकता ना होकर ग्रामीणों व आमजन को सीधे राहत पहुंचाने वाली पहल है। निश्चित रुप से यह सराहनीय पहल मानी जानी चाहिए।

एक खास बात यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की यात्रा में जहां काफिले को सीमित किया गया हैं वहीं दौरों के दौरान ईवी वाहन का उपयोग कर ईंधन बचत पर जोर दिया जा रहा सरकारी स्कूल में ही रात्रि विश्राम से गांववासियों और आमजन में एक अपनेपन का संदेश जा रहा है। लगता है जैसे मुख्यमंत्री अपनो के बीच अपनेपन के साथ मिल रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं और आवश्यकता के अनुसार समाधान भी कर रहे हैं। इसके साथ ही स्थानीय सरकारी मशीनरी मुख्यमंत्री की रात्रि चौपाल को देखते हुए एक्टिव मोड पर आ जाती है और इसका परिणाम यह होता है कि बहुत सी समस्याओं का समाधान तो मुख्यमंत्री की रात्रि चौपाल से पहले ही हो जाता है।

मुख्यमंत्री के दौरे और फिर रात्रि चौपाल की हो तो फिर किसी एक विभाग तक बात सीमित ना रहकर सभी आधारभूत सुविधाओं और समस्याओं के समाधान की हो जाती है और निश्चित रुप से समस्याओं का समाधान होता भी है। इस सबसे अलग ग्राम विकास चौपाल के माध्यम से मुख्यमंत्री और सरकार को लोगों की भावनाओं, क्षेत्र विशेष की समस्याओं, आवश्यकताओं को समझने का अवसर मिलता है वहीं स्थानीय प्रशासन, कानून व्यवस्था आदि का भी चर्चा से फीड बैक मिल जाता है। यह तो सभी जानते हैं कि सभी गांवों में मुख्यमंत्री की ग्रामीण चौपाल नहीं हो सकती पर ग्रामीण चौपाल के माध्यम से संवेदनषील सरकार का संदेश आमजन में जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि विकसित राजस्थान का सपना पूरा करने में यह ग्रामीण विकास चौपाल अहम् भूमिका निभाएगी ही साथ ही सरकार की भावी योजनाएं करते समय फील्ड का यह व्यावहारिक अनुभव निश्चित रुप से कागजी नहीं रह पायेगा और इससे व्यावहारिक योजनाएं बनने के साथ ही विकास को नई गति मिल सकेगी। यह साफ हो जाना चाहिए कि यह किसी मुख्यमंत्री या राजनेता के महिमा मंडन का प्रयास ना होकर एक राजनेता से आमजन की अपेक्षाओं पर खरा उतरने व आमजन के प्रति सीधे संवाद और जनभावना को समझने का बेहतरीन प्रयास माना जाना चाहिए। आज आमजन अपने जनप्रतिनिधि व मुख्यमंत्री से यही अपेक्षा रखती है कि वहां तक आमजन की सहज पहुंच हो सके। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की इस पहल की सराहना की जानी चाहिए और संभव हो तो अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों व जनप्रतिनिधियों को भी इस दिशा में पहल करनी चाहिए।

तपती धरती, झुलसता जीवन: जनता के समक्ष हीटवेव की चुनौती

ललित गर्ग

वर्ष 2026 की गर्मी केवल एक मौसमीय घटना नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के सामने खड़ी एक गंभीर चेतावनी बनकर सामने आई है। अप्रैल-मई के दौरान भारत सहित दक्षिण एशिया के अनेक हिस्सों में पड़ी रिकॉर्ड हीटवेव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जलवायु परिवर्तन अब भविष्य का संकट नहीं, वर्तमान की भयावह वास्तविकता है। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य भारत के अनेक क्षेत्रों में तापमान 46 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कई शहरों में बिजली की मांग ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। सड़कें सूनी दिखने लगीं, श्रमिकों का श्रम ठहरने लगा और बच्चों, बुजुर्गों तथा गरीब तबकों के सामने जीवन बचाने की चुनौती खड़ी हो गई। यह संकट अचानक नहीं आया। यह दशकों से प्रकृति के साथ किए गए असंतुलित व्यवहार, अंधाधुंध शहरीकरण, जंगलों की कटाई, संसाधनों के दोहन और सुविधावादी जीवनशैली का परिणाम है। प्रकृति ने बार-बार संकेत दिए, लेकिन विकास की अंधी दौड़ में हमने उन संकेतों को अनसुना किया। आज वही उपेक्षित चेतावनियां लू बनकर हमारे सामने खड़ी हैं। हीटवेव का सबसे बड़ा कारण केवल बढ़ता तापमान नहीं, बल्कि वह विकास मॉडल है जिसने धरती की प्राकृतिक ढाल को कमजोर कर दिया। जंगल सदियों से पृथ्वी के प्राकृतिक एयर कंडीशनर रहे हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, वाष्पोत्सर्जन द्वारा वातावरण को शीतल रखते हैं और वर्षा चक्र को संतुलित बनाए रखते हैं। लेकिन विडंबना है कि विकास के नाम पर जंगलों का तेजी से विनाश हुआ। हर वर्ष लाखों हेक्टेयर वन क्षेत्र समाप्त हो रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि स्थानीय स्तर पर तापमान बढ़ा, नमी कम हुई, वर्षा चक्र प्रभावित हुआ और गर्म हवाओं की अवधि लंबी होती गई। आज शहर कंक्रीट के जंगल बन चुके हैं। महानगरों में हरित क्षेत्र सिकुड़ते जा रहे हैं और उनकी जगह सीमेंट, डामर और शीशे की ऊंची इमारतें ले रही हैं। इससे अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव तेजी से बढ़ा है। शहर अब आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कई डिग्री अधिक गर्म हो चुके हैं। कंक्रीट दिनभर सूर्य की ऊष्मा को सोखता है और रात में धीरे-धीरे छोड़ता है। परिणामस्वरूप रातें भी गर्म होती जा रही हैं और शरीर को राहत नहीं मिल पाती। दिल्ली, मुंबई, जयपुर और लखनऊ जैसे शहरों में रात का तापमान पहले की तुलना में लगातार बढ़ रहा है। गरीब बस्तियों में स्थिति और भी गंभीर है। वहां न हरित क्षेत्र हैं, न पर्याप्त जल आपूर्ति, न शीतलन के साधन। टीन की छतों वाले घर दिन में भट्ठी बन जाते हैं। गर्मी की मार सामाजिक असमानता को और गहरा करती है। अमीर वर्ग एयर कंडीशनर और बंद कमरों में राहत खोज लेता है, लेकिन मजदूर, रिक्शाचालक, रेहड़ी वाले और निर्माण कार्य में लगे श्रमिक खुले आसमान के नीचे झुलसते रहते हैं। विडंबना यह भी है कि गर्मी से राहत का सबसे लोकप्रिय साधन एयर कंडीशनर स्वयं संकट को बढ़ाने वाला कारक बनता जा रहा है। एक एयर कंडीशनर कमरे को ठंडा करता है, लेकिन बाहर उतनी ही गर्म हवा छोड़ता है। इसके साथ ही बिजली की खपत बढ़ती है, जिसका बड़ा हिस्सा अभी भी कोयला आधारित ऊर्जा से आता है। रेफ्रिजरेंट गैसें अतिरिक्त ग्रीनहाउस प्रभाव पैदा करती हैं। इस प्रकार एक दुष्चक्र निर्मित हो गया है-गर्मी बढ़ती है, एसी बढ़ते हैं, उत्सर्जन बढ़ता है और फिर गर्मी और बढ़ जाती है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव केवल तापमान तक सीमित नहीं है। यह कृषि, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर भी व्यापक असर डाल रहा है। वैज्ञानिक अध्ययनों से संकेत मिले हैं कि बढ़ती गर्मी और अनिश्चित मौसम के कारण गेहूं, धान और अन्य फसलों की उत्पादकता प्रभावित हो रही है। गर्म हवाएं पौधों की वृद्धि रोकती हैं, जल स्रोतों को सुखाती हैं और मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित करती हैं। यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले वर्षों में खाद्य संकट भी गहरा सकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी इसका गंभीर प्रभाव दिख रहा है। लू लगना, निर्जलीकरण, हीट स्ट्रोक, हृदय रोग और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। अस्पतालों में गर्मी से जुड़ी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ रही है।

साफ घर स्वस्थ घर

घर की उचित साफ-सफाई न होना भी तनाव का कारण बन सकता है। यह जानकर शायद आपको हैरत होगी कि कुछ लोगों में खासतौर पर महिलाओं में अपने घर और परिवार के सदस्यों द्वारा साफ-सफाई के संबंध में की जाने वाली लापरवाही तनाव और उच्चरक्तचाप का कारण भी बन जाती है।

हालांकि यह बात स्वभावगत है पर स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखें तो पर्सनल हाइजिन के साथ-साथ घर और अपने आस-पास की सफाई बेहद जरूरी है। यह न सिर्फ स्वास्थ्यवर्धक है, बल्कि अच्छा रहन-सहन बनाए रखने के लिए भी जरूरी है।

घर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप यह जानें कि आपके घर में कौन-कौन सी ऐसी जगह हैं, जिनका कीटाणुओं और छोटे-छोटे जीवों को निमंत्रण करने में प्रमुख योगदान है। किचन में बनी नाली और वॉशबेसिन के आसपास पानी एकत्रित होना और सफाई न रहना, कुकिंग गैस, सिंक, रसोई में साफ-सफाई के लिए इस्तेमाल में आने वाले कपड़ों को नियमित साफ नहीं करना कीटाणुओं को बुलावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

साथ ही फर्श के अलावा घर का फर्नीचर, कारपेट, फूलदान, पंखे, ट्यूबलाइट आदि चीजों की नियमित साफ-सफाई बेहद जरूरी है। ध्यान रखें कि यहां पानी एकत्रित न हो साथ ही गंदगी न फैले। इसके उचित उपायों को अपनाते हुए घर को स्वच्छ और कीट, मच्छर से रहित रखने का प्रयास करें। यदि समय और ऊर्जा की बचत करना चाहते हैं तो एक अच्छे क्लीनर की मदद लें। यदि आपके नियमित इस्तेमाल की वस्तुएं धूल और मिट्टी से मुक्त हैं तो आपका घर कीट और गंदगी में पनपने वाले जीवों से भी मुक्त होगा। जाहिर है कि आप इसके साथ आने वाली कई बीमारियों को अपने घर में प्रवेश करने से रोक पाएंगे। साफ-सुथरी जगह मानसिक शांति देती है और अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं।

दिमाग को सक्रिय करता मोबाइल

अक्सर आपने युवाओं को फोन से चिपके देखा होगा। उन्हें देखते ही आपके मन में एक ही ख्याल आता है कि बहुत ज्यादा मोबाइल फोन पर चिपके रहने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है लेकिन आपको बता दें कि आपकी ये धारणा गलत है। हाल ही में अमेरिका के नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट ने कुछ दिलचस्प तथ्यों को खोज निकाला है।

दिमाग की सक्रियता बढ़ाता फोन

शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला मोबाइल फोन दरअसल दिमाग को अलग-अलग रूपों में प्रभावित करता है। अध्ययन के अनुसार, जो लोग मोबाइल से लंबे समय तक बात करते रहते हैं उनके दिमाग अधिक सक्रिय हो जाता है। इस बात को पुख्ता करने के लिए 47 वर्ष तक के लोगों पर लगभग एक साल तक परीक्षण किया गया। मोबाइल को प्रतिभागियों के दोनों कानों पर कुछ-कुछ समय के लिए प्रयोग करवाया गया। बारी-बारी से दोनों साइड्स पर 50-50 मिनट मोबाइल का प्रयोग करवाया गया। इनमें से कुछ ऐसे प्रतिभागी भी थे जो मोबाइल फोन का प्रयोग करना नहीं जानते थे।

क्या कहता है शोध

ये शोध के परिणाम पीईटी (पोजीट्रान एमिशन टोमोग्राफी) के द्वारा जांचे गए। जिसमें पाया गया कि मनुष्य के दाईं तरफ टेम्पोनरल पोल के मोबाइल के एंटीना के संपर्क में आते ही ओरबिटोफ्रंटल कॉरटैक्स में 7 फीसदी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। हालांकि ये अभी तक साबित नहीं हुआ है कि ग्लूकोज का बढ़ना खतरनाक है या नहीं। प्रमाणित सबूतों में ये बात साफ जाहिर है कि ग्लूकोज मोबाइल एंटीना का टेम्पोपरल पोल के संपर्क में आते ही बढ़ता है। मनोचिकित्सक का कहना है कि मनुष्य में बढ़ने वाले इस ग्लूकोज से फायदा पहुंचता है या नहीं लेकिन इसका नुकसान कुछ नहीं होता।

पूजन से पहले क्यों बजाते हैं घंटी?

क्या आप जानते हैं कि मंदिरों में घंटियां क्यों होती हैं? यह परंपरा बहुत प्राचीन है। इसके पीछे मात्र परंपराएं ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक रहस्य भी हैं। जापान के बौद्ध मंदिरों में भी विशेष प्रकार की घंटियां होती हैं। श्रद्धालु इन्हें बजाकर अपने इष्ट देव के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। इनसे बहुत मधुर ध्वनि निकलती है। मंदिर की घंटी बजाने से विशेष प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। जब वातावरण में इनका प्रसार होता है तो ये नकारात्मकता को दूर करती हैं और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं। इससे मंदिर के आसपास का माहौल शांत और सुखद बनता है। लोगों को एक खास किस्म की आध्यात्मिक शांति मिलती है। अध्यात्म में माना जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह मन के अलावा वातावरण को भी प्रभावित करती है। जिस देश या घर में अशांति का माहौल होता है, वहां नकारात्मकता तेजी से पनपती है। घंटी का एक फायदा यह होता है कि इससे किसी अजनबी को भी यह ज्ञात हो जाता है यहां देवमंदिर है। इससे उसका शीश भगवान के सम्मान में झुक जाता है। शास्त्रों के अनुसार, घंटी बजाना दैवीय शक्ति को नमन करना है।

> दूसरों की गलती पर उन्हें माफी देना भले ही आसान हो लेकिन बात जब खुद को माफ करने की आती है तो शायद यह हमारे लिए आसान नहीं होता, क्योंकि इस बार गलती हमने की और इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। अपराध बोध की भावना थोड़े समय के लिए ठीक है, इसे हावी न होने दें, नहीं तो परेशानी बढ़ेगी। इंसान से गलतियां हो सकती हैं, इससे सीख लीजिए, खुद को माफ कीजिए, खुशी बनी रहेगी।

खुद को माफ करें...

श्रीमद भागवत में एक कहानी है राजा अजामिल की। उस राजा में अनेकों दुर्गुण थे। जब वह अपनी मृत्यु शैया पर पहुंचा तो उसने अपने पुत्र को बुलवाया जिसका नाम नारायण था और जब राजा ने ईश्वर के नाम का उच्चारण किया तो उसे मुक्ति प्राप्त हुई। यह कहानी लोगों में विश्वास जगाती है कि उनका अतीत कैसा भी क्यों न हो,पछतावा करने या अपराधी महसूस कर समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं। यदि तुम अंतिम क्षण में भी ईश्वर की ओर मुड़ते हो, तो तुम्हारे मुक्त होने की संभावना है। यह कहानी सिखाती है कि अतीत में की गई भूलों के प्रति अपराधबोध से ग्रसित नहीं होना है। जब हम मासूम होते हैं और वर्तमान क्षण में टिके रहते हैं तब अपनी भूल का अहसास हो जाता है। ऐसे में हम पहले से ही उस भूल से बाहर निकल जाते है। अतीत के बारे में सोचते रहने के बजाय बस जाग जाओ और उसे स्वीकार करो।आगे बढ़ जाओ और दूसरों पर या स्वयं पर दोषारोपण में मत फंसों।

सामाजिक भावना

हमारा अपराधबोध एक तरह से वह सामाजिक भावना भी है, जिसमें हम सबके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। संबंधों को बचाए रखना चाहते हैं। पर परेशानी यह है कि हम अपने घावों को भरने की जगह उन्हें कुरेदते रहते हैं। जिंदगी में हार, इनकार, उपेक्षा, निराशा और शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है, पर जब ऐसा कई बार होता है तो हम खुद को ही समस्या मानने लगते हैं। खुद को सजा देने के सिलसिले में ऐसे कदम उठाते हैं, जिनका असल समस्या से ताल्लुक ही नहीं होता। जैसे, वजन कम नहीं हो रहा या मानते हैं कि सुंदर नहीं हैं, तो गुस्से में अपना ध्यान रखना ही छोड़ देते हैं, सबसे अलग थलग रहते हैं। अधिक खर्च करने की आदत पर गुस्साते हैं, पर अपने भविष्य के प्रति लापरवाह भी हो जाते हैं। हर समय दूसरों की प्रशंसा और भलाई बटोरने का भाव एक ऐसा जहर है, जो मन में अपनी कमियों का बोझ बढ़ाता जाता है। क्या उस तरफ बढ़ना ठीक है, जो खुद के लिए हीनता और शर्मिंदगी को बढ़ाता है? खुश रहना है तो खुद को गलत मानते रहने के चक्र को तोड़ना जरूरी है। खुद को साथ-साथ माफ करना भी सीखें।

अपनी क्षमता और रुचि के अनुसार सुधार करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें।

माफी का महत्व

आपने अपने जीवन में कई लोगों को माफ किया होगा, माफ करने के बाद आपके अंदर अलग तरह का अनुभव आया होगा। इसका मतलब यह है कि माफी से व्यक्ति को ऊर्जा तो मिलती है साथ ही मद में किसी प्रकार की कुंठा नहीं रहती। तो माफी के महत्व को जरूर समझें।

चुनौती की तरह न लें

आपने गलतियां की हैं तो खुद को माफ भी करें, खुद को सजा देने के बारे में हर वक्त न सोचें। गलतियां इनसानों से होती हैं और ऐसे में खुद को माफ करना उस गलती से निकलना और उसे न दोहराने की कवायद है। अगर आप खुद को माफ नहीं करेंगे तो इससे आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ेगा।

भावनाओं को भी स्वीकारें

सभी के अंदर भावनाएं होती हैं और वे समय और परिस्थिति के अनुसार दिखाई भी देती हैं, आप भी इससे अछूते नहीं हैं। तो अपने क्रोध, भय, प्रेम, सहानुभूति आदि भावनाओं को स्वीकार करें। ये आपको खुद को माफ करने में मददगार साबित होंगी।

संपूर्ण कोई नहीं

शायद ही इस जहां में कोई ऐसा हो जो परफेक्ट यानी संपूर्ण हो, सबके अंदर कोई न कोई कमी जरूर है। अगर आप भी अपनी महात्वाकांक्षा के उड़ान पर हैं और आगे बढ़ने की कोशिश में गलतियां किए जा रहे हैं तो यह स्वाभाविक है। अगर आपसे गलतियां हुई हैं तो इसे दूर कर फिर से कोशिश कीजिए। पुरानी गलतियों को लिए अगर आपने खुद को माफ कर दिया तो यह आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित भी करेगा।

दूसरों को हावी न होने दें

कई बार आप खुद को माफ करना चाहते हैं लेकिन माफ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दूसरों की भावनाएं आपके ऊपर हावी होती हैं। यानी आपकी छवि आपके प्रकृति के अनुरूप है। तो ऐसे में कोशिश करें कि दूसरों की भावनाओं और उनके विचार को खुद पर हावी न होने दें, हमेशा खुद की सुनें और अपने प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करें।

खुद को सजा न दें

प्यार में धोखा खाने वालों को अक्सर लगता है कि उन्होंने अपने दिल की नहीं सुनी और आकर्षण में खुद की भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया। बाद में जब उनका दिल टूटता है तो वे खुद को दुःख देने लगते हैं, खुद को ही प्रताड़ित करते हैं। ऐसा बिलकुल न सोंचे, जो हुआ वह उस समय की मांग थी और आपसे गलती हो गई, वर्तमान में आप जो भी हैं उसपर ध्यान दें और अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।

बदलाव की बयार बहने दें

बदलाव समाज का सच है और वक्त दर वक्त यह बदलाव होता रहता है। ऐसे में आप कैसे पिछड़ सकते हैं, बदलते समाज और बदलते सामाजिक वातावरण के साथ खुद के अंदर भी बदलाव करें। यह भी सोचें कि इस बदलाव का असर आपके जीवन में क्या होगा, और क्या पता इससे आपकी काया ही पलट जाए और सफलता के नये आयाम तक पहुंच जाएं।

संतुलन बहुत जरूरी

जीवन में समता यानी संतुलन बहुत जरूरी है, लेकिन अधिकांश लोगों का जीवन असंतुलित बना हुआ है। हमने एक ऐसी मानसिक स्थिति का निर्माण कर रखा है कि सुख की स्थिति आने पर हम खुशी से उछल जाते हैं और दुःख की स्थिति में मानो मुरझा जाते हैं जबकि हमें हर स्थिति में एक सा रहना चाहिए। सुख के साथ अहं और दुख के साथ हीनता की ग्रंथि जुड़ जाती है जो हमारे दुखों का मूल है। दुखी व्यक्ति हीन भावना से ग्रस्त होता है और इतना ग्रस्त होता है कि वह निराशा का जीवन जीने लगता है। वह सोचता है, यह संसार मेरे जीने योग्य नहीं है। जीवन में मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। सारा जीवन बेकार है।

सुख के साथ अहं की ग्रंथि

सुख के साथ अहं की ग्रंथि घुलती है और अब आदमी स्वयं को सम्राट मानकर जीता है। यह अहं भावना उसमें अनेक कुंठाएं पैदा करती हैं। निंदा होती है, आदमी घबरा जाता है, दुखी बन जाता है। प्रशंसा के दो शब्द सुनता है, खुशी से फूल जाता है तब उसे बोलने का पूरा विवेक नहीं रहता। वह अहंकार से ग्रस्त हो जाता है। इस प्रकार अनेक द्वंद्व हैं, जिनकी परिक्रमा हर इंसान कर रहा है। ये सारे द्वंद्व चित्त की स्थिति को विषम बनाए हुए हैं। चित्त की इस विषमता का नाम ही है संसार। हमारी अंतस-चेतना का सुझाव सदा समता की ओर रहता है, किंतु व्यवहार का गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र है कि वह विषमता की ओर खिंचता है।

लक्ष्य को हमेशा याद रखें

जो व्यक्ति समता के साथ जीते हैं उन्हें महान आदर्श माना गया है। यह जिंदगी केवल सुख-सुविधाओं के पीछे पागल बनकर खराब करने के लिए नहीं है। जीवन का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। अपनी जिंदगी के उस दूरगामी और ऊंचे लक्ष्य को हमेशा याद रखें और उसी पर अपनी तीव्र दृष्टि टिकाए रखें। अगर इन छोटी-मोटी सुविधाओं को ही जीवन का सार मान लिया जाए तो अपने विपुल वैभव को आप कौड़ियों में गंवा बैठेंगे। अपने इस विपुल खजाने को आप पहचानें, जो प्रकृति से विरासत में मिला है। इस मनुष्य शरीर के साथ मिली महान दैवी शक्तियों का वास्तविक और सही-सही उपयोग तब होगा जब आप ऐसा ऊंचा लक्ष्य बनाएंगे जिसे पाकर इस मनुष्य जीवन का मिलना सार्थक हो जाए। याद रखें, जीवन की सार्थकता भौतिक वस्तुओं या पदार्थों के जरिए उपलब्ध नहीं हो सकती।

गलती को स्वीकारें

खुद को माफ करने की कवायद करने से पहले जरूरी है कि आपने जो गलती की है उसे स्वीकार करें। क्योंकि आपने उस वक्त अपने विवेक से काम नहीं लिया और भावनाओं में बहकर, क्रोध और गुस्से में आकर गलती कर दी। इस बात को समझकर अपनी गलती को स्वीकार कीजिए। सामान्यतः हम अपनी भूलों को उचित ठहराते हैं ताकि अपराध का बोध न हो, पर से काम नहीं बनता। चाहे जो भी औचित्य हम दें अपराधबोध टिका रहता है। हम अपराधबोध का प्रतिरोध करते हैं और वह बना रहता है और फिर कहीं अन्तर की गहराई से हमारे व्यवहार को विकृत कर देता है। हमें अपने द्वारा की गई भूलों के लिए अपराधी महसूस करने का पूरा पूरा अधिकार है। पूर्ण रूप से दुखी बन जाओ पूरे एक मिनट,दस मिनट या पच्चीस मिनट के लिए, लेकिन उससे अधिक नहीं और फिर हम उससे बाहर निकल जाएंगे। भूल को सही साबित करने की बजाय उसे स्वीकार करो। औचित्य सिद्ध करना बहुत सतही है क्योंकि यह अपराधबोध को नहीं हटाता, बल्कि वह हमें अपराध का और भी अधिक बोध कराता है।अपने अपराधबोध के साथ सौ प्रतिशत रहो और वह पीड़ा एक ध्यान की तरह बन जाएगी और अपराधबोध से भारमुक्त करेगी।

खुद को रखें स्ट्रेस फ्री...

वर्किंग लेडी कॉन्सेप्ट से हमारे मन में स्त्रियों की एक स्वच्छंद छवि बन जाती है। यह टर्म उन स्त्रियों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है जो कि बेहद कुशलता से घर और बाहर की दोहरी जिम्मेदारियां निभा रही हों। ऑफिस, घर, सहकर्मी और परिवार को संभालने वाली स्त्रियों को मल्टीटास्कर कहा जाता है। उनसे जुडे लोगों के लिए वे सुपरवुमन से कम नहीं होती हैं। उनकी परेशानियों को हर कोई समझता भी नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी समस्याएं साझा करने की ज्यादा आदत नहीं होती है। पर कभी-कभी आत्मनिर्भर स्त्रियों को भी दोहरी भूमिका निभाते-निभाते अवसाद होने लगता है। जानते हैं वर्क स्ट्रेस के कारण और उसके निवारण के उपाय।

वास्तविकता समझें

आपको यह समझना चाहिए कि ऑफिस का काम आपकी जिंदगी का जरा सा हिस्सा मात्र है। अपनी पूरी एनर्जी को उसमें ही डाल देने का नकारात्मक प्रभाव आपके निजी रिश्तों पर पड सकता है। फेमिली और प्रोफेशन में सही संतुलन बना कर चलें।

करें अपने मन की

आपके अति व्यस्त जीवन में आप खुद को भूलने लगती हैं। कभी-कभी समय निकाल कर अपना विश्लेषण करें। अपनी पसंद-नापसंद, हुनर को समझें और समय दें। पुराने एलबम देखकर भूली-बिसरी यादें भी ताजा कर सकती हैं।

परिवार को भी दें समय

ऑफिस का काम घर पर लेकर न आएं। बचा हुआ सारा समय खुद को व परिवार को समर्पित कर दें, वर्ना परिजन उपेक्षित महसूस करेंगे। डिनर के बाद सबके साथ टहलने जा सकती हैं या बच्चों का होमवर्क करवाएं।

रोज एक ही दिनचर्या अपनाने से बेहतर है कि बीच-बीच में थोडा बदलाव करती रहें। अपने काम से ब्रेक लेकर अपने परिजनों या दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाएं। एक ही टाइमटेबल पर काम करते रहने से बोरियत होने लगती है, इसलिए कुछ बदलाव जरूरी होता है।

सकारात्मक सोच

नकारात्मक विचारों से भी तनाव बढ़ता है। कोशिश करें कि ऐसे विचारों को दूर ही रखें। परफेक्शन के बजाय अपना बेस्ट देने का हरसंभव प्रयास करें। आप मोटिवेशनल किताबें भी पढ सकती हैं। न नहीं कह पाने की आदत की वजह से अपने ऊपर काम का बोझ न बढाती रहें। काम उतना ही करें, जितना आपके बस में हो। इससे आपका तनाव कम होगा और परिवार के लिए समय भी बचा सकेंगी।

वर्कप्लेस पर एक्सरसाइज

अपनी दिनचर्या ऐसे निर्धारित करें कि उसमें फिजिकल वर्क भी शामिल हो। लिफ्ट के बजाय सीढियों का प्रयोग करें। लंच ब्रेक के दौरान वॉक करने की आदत डालें।

रिलैक्स रहें

आराम करने का मतलब सिर्फ वेकेशन पर जाना नहीं होता है। हर 4 से 5 घंटे में दो मिनट के लिए आंखें बंद कर आप खुद को रिलैक्स कर सकती हैं। अगर कंप्यूटर पर ज्यादा काम करना पडता हो, तो बीच-बीच में आंखें बंद करके गहरी सांस लेते रहें।

सोशल नेटवर्क बनाएं

अपनी व्यस्तता के बीच में भी दोस्तों व पडोसियों के लिए समय जरूर निकालें। इससे आपका मूड और माहौल दोनों बदल जाएंगे। उनके साथ घुलने-मिलने से आप रिलैक्स महसूस करेंगी और काम में अपना बेहतर आउटपुट भी दे सकेंगी।

मी टाइम है जरूरी

जब आप वेकेशन पर जाएं, अपने लैपटॉप व फोन से थोडी दूरी बना कर रहें। खुद के साथ समय बिताने की आदत डालें। सिर्फ परिवार या ऑफिस में ही व्यस्त रहेंगी तो स्ट्रेस बढेगा। जितना हो सके, खुश रहें और खुद के लिए भी वक्त निकालें। ज्यादा स्ट्रेस लेने से आप न तो अपने परिवार पर ध्यान दे पाएंगी, न ही ऑफिस के कामों पर। बीच-बीच में रिफ्रेश होते रहने से बैलेंस बना रहेगा।

गॉसिप में न उलझें

ऑफिस में माहौल तनावपूर्ण न बनने दें। माहौल ऐसा रखें कि सब बिना टेंशन के काम कर सकें। गॉसिप में उलझने के बजाय बेहतर काम करने के तरीकों पर चर्चा करें। अगर आपको लग रहा हो कि किसी के घर में कोई परेशानी है, किसी की तबियत खराब है या कोई यूं ही टेंशन में है तो उसकी मदद करने की कोशिश करें। फ्री टाइम मिलने पर अपने सहयोगियों से बात जरूर करें। इससे सब एक-दूसरे को बेहतर ढंग से समझेंगे और कोई मुसीबत आने पर साथ भी खडे होंगे।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

प्रतिदिन हो रही जनता की जेब पर डकैती: खरगे

नयी दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि फ्यूल लूट का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है और पिछले 10 दिनों में चौथी बार पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं।श्री खरगे ने कहा कि पिछले दो सप्ताह में पेट्रोल की कीमतों में कुल 7.35 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 7.53 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने आम लोगों की बचत को जलाने के लिए पेट्रोल छिड़क दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच संयुक्त प्रगतिशील गंठबंधन सरकार के दौरान अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में 175.34 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में अंतरराष्ट्रीय क्रूड ऑयल की कीमतों में कोई उल्लेखनीय बढ़ोतरी नहीं हुई।

कच्चे तेलों में गिरावट, फिर दाम क्यों बढ़ा रहे सरकार: सुरजेवाला

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोमवार को पेट्रोल-डीजल कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला और आरोप लगाया कि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद वह आम आदमी की जेब काट रही है।

सुरजेवाला ने कहा कि आज कच्चे तेल की कीमत गिरकर 98.6 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हो गई है। बीजेपी पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में 2.71 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करके आम आदमी की जेब काट रही है। हमारे पास इस बारे में एक बड़ा खुलासा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक कच्चे तेल के बाज़ारों में लगातार उतार-चढ़ाव और पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के बीच, दो हफ़्ते से भी कम समय में यह चौथी बढ़ोतरी है। ताज़ा संशोधन के बाद, दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए के आंकड़े को पार कर गईं, इसमें 2.61 रुपए की बढ़ोतरी हुई।

श्रीकांत वर्मा हिंदी के पहले सबसे नाराज कविः अशोक

नयी दिल्ली। प्रसिद्ध कवि, आलोचक, कला-मर्मज्ञ एवं रजा फाउंडेशन के ट्रस्टी अशोक वाजपेयी ने मगध जैसी क्लासिक कृति के कवि श्रीकांत वर्मा को उनकी 40वीं पुण्यतिथि के अवसर पर याद करते हुए उन्हें हिंदी का एक नाराज कवि बताया और कहा कि उन्होंने अपनी वैचारिकता और तेवर से समझौता कभी नहीं किया।श्री वाजपेयी ने सोमवार को यहां कांस्टीट्यूशन क्लब में आयोजित विश्व हिंदी परिषद एवं श्रीकांत वर्मा ट्रस्ट द्वारा श्रीकांत वर्मा स्मरांजलि में उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचार व्यक्त करते हुए श्री वाजपेयी ने श्रीकांत वर्मा के साथ बिताए समय और उनसे जुड़ी अविस्मरणीय साहित्यिक यादों को जीवंत किया। उन्होंने कहा श्रीकांत वर्मा एक लड़ाकू कवि थे। किसी भी सभा में वे अपने वैचारिक और कविता के तेवर को स्थगित नहीं करते थे। वे जो कहना चाहते थे, कह देते थे। वो हिंदी के पहले सबसे नाराज कवि थे। वे अपने नरक में अकेले थे। वे 20वीं सदी के अंधेरे की शिनाख्त करने वाले पहले कवि थे।

एथेनॉल आधारित स्टोव से सस्ता होगा खाना बनानाः गडकरी

नई दिल्ली । केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश में विकसित एथेनॉल आधारित स्वदेशी कुकिंग स्टोव तकनीक का अनावरण करते हुए दावा किया है कि इस तकनीक से खाना बनाने की लागत एलपीजी गैस की तुलना में कम होगी। नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यह तकनीक न केवल घरेलू ऊर्जा खर्च को कम करने में मदद करेगी, बल्कि भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम साबित हो सकती है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने युवाओं में विज्ञान और नवाचार के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए 40 करोड़ रुपये की नई परियोजना शुरू करने की भी घोषणा की। गडकरी ने बताया कि इस नए स्टोव में एथेनॉल और पानी के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि केवल 7 प्रतिशत एथेनॉल को पानी में मिलाकर ऐसी लौ तैयार की जा सकती है, जो खाना पकाने के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। उनके अनुसार यह तकनीक पूरी तरह स्वदेशी है।

चार साल बाद दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपये के पार

नयी दिल्ली। पश्चिम एशिया संकट के बीच तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ा दिये हैं और दिल्ली में चार साल बाद पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज से गैर-ब्रांडेड यानी सामान्य पेट्रोल 2.61 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। अब इसकी कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर हो गयी है। सामान्य डीजल भी अब 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। इसकी कीमत में 2.71 रुपये का इजाफा किया गया है। दोनों जीवाश्म ईंधनों का यह 21 मई 2022 के बाद का उच्चतम स्तर है। इस साल 15 मई से अब तक चार बार में दिल्ली में पेट्रोल 7.35 रुपये और डीजल 7.53 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है। इनके दाम 30 अक्टूबर 2024 के बाद गत 15 मई को पहली बार बढ़ाये गये थे।दिल्ली में इंडियन ऑयल के प्रीमियम पेट्रोल एक्सपी95 की कीमत भी 2.61 रुपये बढ़कर 109.24 रुपये और प्रीमियम डीजल एक्सजी की कीमत 2.71 रुपये बढ़कर 100.52 रुपये प्रति लीटर हो गयी है। कोलकाता में पेट्रोल 2.87 रुपये और चेन्नई में 2.46 रुपये महंगा हुआ है।

सरकार गिर जाएगी वाले बयान पर भाजपा का पलटवार

भस्मासुर राहुल अराजकता फैला रहे : गौरव भाटिया

नईदिल्ली। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए उन पर टूलकिट पॉलिटिक्स फैलाने और केंद्र सरकार की स्थिरता के बारे में गैरजिम्मेदाराना टिप्पणियां करने का आरोप लगाया। भाटिया ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। ये टिप्पणियां राहुल गांधी के उस बयान के बाद आईं, जो उन्होंने कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग की सलाहकार परिषद की बैठक के दौरान दिया था, जहां उन्होंने दावा किया था कि यदि मौजूदा आर्थिक स्थिति बनी रहती है, तो सरकार अगले साल तक नहीं टिक पाएगी।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष के नाम से सामने आए हालिया राजनीतिक बयानों पर बोलते हुए भाटिया ने सरकार के गिरने के दावों को बार-बार दोहराई जाने वाली गलत सूचना बताया। उन्होंने कहा कि कल एक और 'विवाद' सामने आया, जिसमें कहा जा रहा है कि यह सरकार, जो पूरी ताकत से देश की सेवा कर रही है, एक साल के भीतर गिर जाएगी। मैं सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि 'भस्मासुर राहुल गांधी' - हमें नहीं पता था कि भस्मासुर ज्योतिषी भी बन जाएंगे।

भाटिया ने राहुल गांधी की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना करते हुए उन्हें विरोधाभासी और भ्रम पैदा करने का प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में एक बैठक में कुछ टिप्पणियां कीं और बाद में बाहर एक अलग बयान जारी किया, जिस पर चर्चा हो रही है। इसे दुर्भाग्यपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व वर्तमान में आर्थिक मंदी और संकट का सामना कर रहा है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा नेतृत्व में भारत स्थिर बना हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, यह वैश्विक संकट का समय है और दुनिया भर के कई देश आर्थिक अस्थिरता का सामना कर रहे हैं।

उनकी अर्थव्यवस्थाएं काफी कमजोर हो गई हैं। वहीं दूसरी ओर, पिछले 85 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने मजबूत लचीलापन दिखाया है। भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत और स्थिर बनी हुई है। भाटिया ने यह कहते हुए अपना भाषण समाप्त किया कि अस्थिरता पैदा करने के प्रयास विफल होंगे। उन्होंने कहा कि यदि राहुल गांधी का इरादा अराजकता फैलाना है, तो हमारा संकल्प भी भारत को और मजबूत बनाना है। आप चाहे जो भी कोशिश कर लें, लेकिन हम भी भारत को आगे ले जाने के लिए उतने ही दृढ़ हैं।

राहुल युवाओं को पीएम मोदी के खिलाफ भड़का रहे

पटना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोमवार को राहुल गांधी की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि वे निराधार टिप्पणियों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ युवाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। गांधी के इस दावे पर सिंह ने जवाब दिया कि बढ़ती महंगाई के कारण भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार एक साल के भीतर गिर जाएगी। सिंह ने कहा कि राहुल गांधी देश को समझ नहीं पा रहे हैं; वे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ देश के युवाओं को भड़काना चाहते हैं और युद्ध छेड़ना चाहते हैं। यह देश प्रधानमंत्री से प्यार करता है; जब भी देश में ऐसी घटनाएं हुई हैं, यह राष्ट्र दृढ़ रहा है। देश प्रधानमंत्री मोदी की (किफायती) अपील पर काम कर रहा है। उन्होंने बिहार के पटना में पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही।

सिंह ने राहुल गांधी को 'राहुल मियां' कहकर संबोधित किया और कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि यह 'माओवादी मुस्लिम कांग्रेस' बन गई है। उन्होंने दोहराया कि देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ है, राहुल गांधी अब कांग्रेस में नहीं हैं; वे 'राहुल मियां' बन गए हैं। उन्होंने इसे माओवादी मुस्लिम कांग्रेस में बदल दिया है, और उन्हें इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए- देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है। राहुल गांधी की ये टिप्पणियां 23 मई को कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग की सलाहकार परिषद की बैठक में आईं, जहां उन्होंने दावा किया कि यदि मौजूदा आर्थिक स्थिति जारी रही, तो सरकार अगले साल तक नहीं टिक पाएगी। बैठक में उपस्थित अन्य लोगों में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, अभिषेक सिंहवी, तारिक अनवर, इमरान मसूद और अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष शायर इमरान शामिल थे। बैठक के बाद, कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने एएनआई को बताया कि राहुल गांधी ने नेताओं से किसी भी समूह के खिलाफ किसी भी प्रकार के अत्याचार या अन्याय को दूर करने का आग्रह किया।

ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र पर बरसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी

जनता की जेब पर लगातार वार: राहुल

नईदिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को केंद्र सरकार की दस दिनों में चौथी बार पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि सरकार चुपचाप नागरिकों की जेबें लूट रही है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव के दौरान पेट्रोल की कीमतें नियंत्रण में रखी गईं, लेकिन अब किश्तों में बढ़ोतरी की जा रही है और यह बढ़ोतरी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महंगाई बढ़ाने वाला मोदी बताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने पहले ही आने वाले आर्थिक तूफान की चेतावनी दी थी, लेकिन आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री उस समय चुनाव प्रचार में व्यस्त थे।

कांग्रेस नेता ने एक्स पर लिखा कि महंगाई बढ़ाने वाले मोदी ने फिर से अपना काम कर दिया है। वे पेट्रोल-डीजल की कीमतें किश्तों में बढ़ा रहे हैं - ताकि आपकी जेबें चुपचाप लूटी जाती रहें। मैं महीनों से आने वाले आर्थिक तूफान की चेतावनी दे रहा हूं। लेकिन मोदी जी, हमेशा की तरह, उस समय चुनाव में व्यस्त थे - और चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 8 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई। उनके पोस्ट में आगे लिखा था कि और यह बढ़ोतरी जारी रहेगी। महंगाई के सरगना मोदी का एकमात्र काम यही है— चुनाव के दौरान वादे करना और बाकी समय जनता की जेब पर हमला करना।

सोमवार सुबह ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि किसानों से लेकर छोटे उद्योगों तक, समाज का हर वर्ग भाजपा द्वारा देश की लूट का खामियाजा भुगत रहा है। खरगे ने ङ्क पर एक पोस्ट में लिखा कि ईंधन की लूट का दैनिक सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि ईंधन की कीमतों में हर बढ़ोतरी घरेलू बजट पर एक और चोट है और इसका अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। किसानों से लेकर लघु एवं मध्यम उद्यमों तक, समाज का हर वर्ग भाजपा की लूट का खामियाजा भुगत रहा है।

हाल के दिनों में लगातार तीन बार कीमतों में बढ़ोतरी के बाद यह नया संशोधन किया गया है। 15 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई। इसके बाद 19 मई को 90 पैसे प्रति लीटर की एक और वृद्धि हुई। 23 मई को पेट्रोल की कीमतों में 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 91 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई। कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में वृद्धि, मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव और पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव से जुड़ी आपूर्ति में बाधाओं की चिंताओं के कारण तेल विपणन कंपनियों पर लगातार दबाव बना हुआ है, जिसके चलते ईंधन की कीमतों में बार-बार वृद्धि की जा रही है।

रूस और ईरान से सस्ता तेल क्यों नहीं खरीद रहे पीएम मोदी : केजरीवाल

दो सप्ताह के भीतर ईंधन की कीमतों में चौथी बार वृद्धि के बाद, आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और ईरान से कच्चा तेल और गैस आयात क्यों नहीं कर रहे हैं, जो काफी सस्ता होगा। एक्स पर केजरीवाल ने लिखा कि तेल की कीमतें फिर से बढ़ गई हैं। फिर भी हम रूस और ईरान से सस्ता तेल नहीं खरीद रहे हैं। मोदी को ऐसी क्या मजबूरी है?

एक वीडियो संदेश में उन्होंने बताया कि पिछले दो हफ्तों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 7.5 रुपये से 8 रुपये तक की वृद्धि हुई है, जबकि अन्य देशों में औसत वृद्धि 2.5 रुपये रही है। उन्होंने कहा कि आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। औसतन, पूरे देश में कीमतों में 2.5 रुपये प्रति पेट्रोल/डीजल की वृद्धि हुई है। पिछले कुछ दिनों में यह चौथी बार बढ़ोतरी हुई है। पिछले 10-15 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 7.5 रुपये से 8 रुपये की वृद्धि हुई है।

केजरीवाल ने पूछा कि जब रूस और ईरान दोनों देश पर्याप्त मात्रा में सस्ते दामों पर तेल और गैस की आपूर्ति करने को तैयार हैं, तो भारत उनसे तेल और गैस क्यों नहीं खरीद रहा है? उन्होंने आगे कहा कि रूस और ईरान हमें सस्ते दामों पर और पर्याप्त मात्रा में तेल और गैस की आपूर्ति करने को तैयार हैं। हम उनसे क्यों नहीं खरीद रहे हैं? दो-तीन दिन पहले मैंने आपसे पूछा था कि क्या हमारे देश को रूस और ईरान से तेल और गैस खरीदना चाहिए। लगभग 97% लोगों ने सहमति जताई कि हमें खरीदना चाहिए।

उन्होंने जनता की मांग और इन देशों द्वारा सस्ते दामों पर आपूर्ति की पेशकश के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इन देशों से तेल और गैस खरीदने में बरती जा रही बाधाओं के पीछे के कारणों पर सवाल उठाया।

खेल
प्रमुख समाचार

फाइनल के टिकट के लिए भिड़ेंगे आरसीबी और गुजरात टाइटंस

धर्मशाला। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 का रोमांच अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। मंगलवार को धर्मशाला में खेले जाने वाले क्वालिफायर-1 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और गुजरात टाइटंस (जीटी) आमने-सामने होंगी। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में जगह बनाएगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर-2 खेलना होगा। दोनों टीमों ने लीग स्टेज में 14 मैचों में 18-18 अंक हासिल किए, लेकिन बेहतर नेट रन रेट के चलते आरसीबी ने टॉप पर रहते हुए क्वालिफायर-1 में जगह बनाई। रजत पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी ने इस सीजन शानदार प्रदर्शन किया है।

विराट कोहली का अनुभव, फिल साल्ट की विस्फोटक शुरुआत और मिडिल ऑर्डर की मजबूती ने आरसीबी को बेहद खतरनाक टीम बना दिया है। फिल साल्ट चोट से वापसी के बाद प्लेऑफ में खेलने के लिए तैयार हैं, जिससे टीम की बल्लेबाजी को और मजबूती मिली है। वहीं जितेश शर्मा, क्रूणाल पंड्या और टिम डेविड जैसे खिलाड़ी भी मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। गुजरात टाइटंस ने इस सीजन अपने संतुलित गेंदबाजी आक्रमण के दम पर प्लेऑफ तक का सफर तय किया है। मोहम्मद सिराज, कैगिसो रबाडा और प्रसिद्ध कृष्णा की तेज गेंदबाजी तिकड़ी नई गेंद से विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाती रही है। वहीं राशिद खान और साई किशोर ने मिडिल ओवर्स में रन गति पर लगाम लगाई है। गुजरात की बल्लेबाजी काफी हद तक कप्तान शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर पर निर्भर रही है। दोनों टीमों के संतुलित प्रदर्शन को देखते हुए क्वालिफायर-1 बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। आरसीबी जहां लगातार दूसरी बार खिताब जीतने की ओर मजबूत कदम बढ़ाना चाहेगी, वहीं गुजरात टाइटंस अपने अनुशासित प्रदर्शन से फाइनल का टिकट हासिल करना चाहेगी।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 1074 अंक चढ़ा निफ्टी 24,032 पर बंद

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजारों में आज तेज खरीदारी देखने को मिली। वैश्विक इक्विटी बाजारों में मजबूती और पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की उम्मीदों के बीच निवेशकों का रुझान सकारात्मक रहा। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते की उम्मीदों ने भी बाजार धारणा को मजबूत किया। कारोबार के अंत में निफ्टी 50 इंडेक्स 312.40 अंक यानी 1.32 प्रतिशत की तेजी के साथ 24,031.70 पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 1,073.61 अंक यानी 1.42 प्रतिशत उछलकर 76,488.96 पर पहुंच गया। बाजार की तेजी में लार्जकैप शेयरों का बड़ा योगदान रहा। निफ्टी 50 में अदाणी इंटरप्राइसेस, आइचर मोटर्स, लार्सन एंड टुब्रो और बजाज फाइनेंस सबसे बड़े गेनर्स रहे। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 0.94% और निफ्टी स्मालकैप इंडेक्स 1.37% की बढ़त के साथ बंद हुए।

10 दिन में चौथी बार बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम

नई दिल्ली। देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी गई है। सोमवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 2.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की। पिछले 10 दिनों में यह चौथी बार है, जब ईंधन की कीमतें बढ़ाई गई हैं। लगातार बढ़ते दामों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। इससे पहले शनिवार को भी पेट्रोल-डीजल के दाम में 87 से 91 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई थी। विशेषज्ञों के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी, कमजोर होता रुपया और आयात लागत बढ़ने की वजह से तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ा है। इसके अलावा रिफाइनिंग मार्जिन में बदलाव का असर भी ईंधन की कीमतों पर पड़ रहा है।

10 ग्राम सोने की कीमत 1,59,000 रुपए के पार

नईदिल्ली। सोमवार (25 मई) को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने-चांदी की कीमतों में उछाल दर्ज किया गया है। आज सोने का भाव 671 रुपए (0.42%) के उछाल के साथ 1,59,350 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वहीं चांदी की कीमत में 4851 रुपए (1.78%) की तेजी आई है, एक किलोग्राम चांदी 2,71,846 रुपए पर कारोबार कर रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में दोनों कीमती धातुओं में बढ़त देखी जा रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हाजिर सोना 4,562.40 डॉलर प्रति औंस रह गया। वहीं, चांदी 2.73 फीसदी की तेजी के साथ 78.28 डॉलर प्रति औंस पर है। इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक, शुक्रवार को बाजार बंद होने के समय 24-कैरेट सोने की कीमत 1,58,120 रुपए प्रति 10 ग्राम (3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज के बिना) थी। इसी तरह 22-कैरेट सोने के दाम 1,54,320 रुपए प्रति 10 ग्राम थे।

गुरुवार को बंद रहेगा शेयर बाजार

नईदिल्ली। शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए यह हफ्ता काफी अहम रहने वाला है। बकरीद (ईद-उल-अजहा) की छुट्टी को लेकर चल रहा असमंजस अब खत्म हो गया है। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर 28 मई 2026 (गुरुवार) को गजेटेड हॉलिडे घोषित कर दिया है। इसके साथ ही यह साफ हो गया है कि 28 मई को भारतीय शेयर बाजार पूरी तरह बंद रहेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों एक्सचेंजों में इक्विटी, डेरिवेटिव्स और अन्य सभी सेगमेंट में ट्रेडिंग नहीं होगी। निवेशकों को अपनी खरीद-बिक्री की रणनीति इस छुट्टी को ध्यान में रखकर बनानी होगी। मई 2026 निवेशकों के लिए छुट्टियों से भरा महीना रहा। महीने की शुरुआत 1 मई की छुट्टी से हुई थी।

पेट्रोल मूल्य वृद्धि का विरोधाभास, ईंधन बना मुनाफे का इंजन

भूपेन्द्र गुप्ता

भारत में पेट्रोल की बढ़ती कीमतें अब केवल अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कहानी नहीं रह गई हैं। वे सरकारों की उस आर्थिक संरचना का प्रतीक बन चुकी हैं जिसमें ईंधन उपभोक्ता की आवश्यकता कम और राजस्व का सबसे भरोसेमंद स्रोत अधिक दिखाई देता है। आज जब ईरान युद्ध और पश्चिम एशिया के तनाव के कारण पेट्रोल की कीमतें फिर बढ़ रही हैं, तब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में जनता केवल वैश्विक संकट का बोझ उठा रही है, या फिर उस कर-व्यवस्था का भी भार झेल रही है जिसने ईंधन को राजस्व मशीन बना दिया है?

भारत जैसे देश में, जहाँ करोड़ों लोग प्रत्यक्ष कर दायरे में नहीं आते, पेट्रोल-डीजल पर लगाया गया टैक्स सरकारों के लिए सबसे आसान आय का साधन बन गया है। उपभोक्ता हर दिन, हर लीटर के साथ टैक्स देता है—बिना किसी बहस, नोटिस या प्रतिरोध के। यही कारण है कि पेट्रोल की कीमत अब केवल ऊर्जा लागत से तय नहीं होती; उसमें सरकारों की राजकोषीय भूख भी शामिल होती है।

वर्तमान मूल्य वृद्धि इसी विरोधाभास को उजागर करती है। सरकारें कह रही हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महँगा हो गया है, इसलिए कीमतें बढ़ना स्वाभाविक है। यह तर्क आंशिक रूप से ही सही है।

भारत लगभग 85 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए वैश्विक संकटों का असर यहाँ पड़ना तय है। लेकिन सवाल यह है कि जब कच्चा तेल सस्ता हुआ था तब जनता को उसी अनुपात में राहत क्यों नहीं मिली? कोविड काल और उसके बाद कई महीनों तक अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें ऐतिहासिक रूप से नीचे चली गई थीं। उस समय जनता को उम्मीद थी कि पेट्रोल-डीजल सस्ते होंगे। लेकिन हुआ उल्टा। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, और राज्यों ने वैट(मूल्य वर्धित टैक्स) बनाए रखा और पेट्रोल के दाम ऊँचे ही बने रहे। सरकारों का राजस्व बढ़ता गया, जबकि उपभोक्ता राहत की प्रतीक्षा करता रहा। यहीं से ऊर्जा लागत मॉडल और राजस्व मॉडल का अंतर स्पष्ट होता है। ऊर्जा लागत मॉडल कहता है कि ईंधन की कीमत मुख्यत: तेल की वास्तविक लागत से तय होनी चाहिए। लेकिन राजस्व मॉडल में ईंधन सरकार के बजट संतुलन का उपकरण बन जाता है। भारत में धीरे-धीरे यही हुआ है। आज भी पेट्रोल की कीमत का बड़ा हिस्सा टैक्स है। यदि पेट्रोल का वास्तविक बेस प्राइस लगभग ?55ङ्क60 प्रति लीटर है, तो उपभोक्ता पंप पर ?110 के आसपास भुगतान करता है। यानी वह केवल पेट्रोल नहीं खरीद रहा है, बल्कि भारी कर-व्यवस्था का वित्तपोषण भी खरीद रहा है।

सबसे बड़ा विरोधाभास तब दिखाई देता है जब सरकारें एक ओर जनता से खर्च कम करने, सादगी अपनाने और वैश्विक संकट सहने की अपील करती हैं, वहीं दूसरी ओर पेट्रोल-डीजल को राजस्व संग्रह के स्थायी साधन की तरह इस्तेमाल करती रहती हैं। यदि वास्तव में संकट साझा है, तो उसका बोझ केवल उपभोक्ता पर क्यों डाला जाए? टैक्स संरचना में स्वत: कमी क्यों नहीं आती?

यह भी ध्यान देने योग्य है कि पेट्रोल-डीजल पर टैक्स एक प्रतिगामी कर (रिग्रेसिव टैक्स) की तरह काम करता है। अमीर और गरीब—दोनों एक लीटर पेट्रोल पर लगभग समान टैक्स देते हैं। लेकिन उसका वास्तविक बोझ गरीब और मध्यवर्ग पर अधिक पड़ता है। डीजल महँगा होते ही परिवहन महँगा होता है, और फिर खाद्यान्न से लेकर निर्माण सामग्री तक सबकी कीमतें बढ़ जाती हैं। यानी ईंधन मूल्य वृद्धि केवल वाहन चलाने वालों की समस्या नहीं रहती , वह पूरी अर्थव्यवस्था में महँगाई का दबाव पैदा करती है।

सरकारों का तर्क है कि इसी राजस्व से सड़कें बनती हैं, कल्याणकारी योजनाएँ चलती हैं और राजकोषीय घाटा नियंत्रित होता है। यह तर्क पूरी तरह गलत नहीं है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या जनता को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार राहत दे, तब उसका लाभ सीधे उपभोक्ता तक पहुँचे? और यदि संकट के समय जनता से त्याग अपेक्षित है, तो क्या सरकारों को भी अपने कर ढाँचे में लचीलापन नहीं दिखाना चाहिए?

उप मुख्यमंत्री शर्मा ने भोरमदेव कॉरिडोर निर्माण का किया निरीक्षण

आदिवासी संग्रहालय के विकास और विस्तार पर जोर

रायपुर। स्वदेश दर्शन योजना के तहत भोरमदेव क्षेत्र में चल रहे 146 करोड़ रुपए के भोरमदेव कॉरिडोर निर्माण कार्य को लेकर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने आज भोरमदेव स्थित सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक ली। बैठक में रायपुर से पहुंचे पर्यटन विभाग के एम डी श्री विवेक आचार्य भी मौजूद रहे। बैठक के पहले उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, निर्माण एजेंसीज के इंजिनियर्स और ठेकेदारों के साथ पूरे प्रोजेक्ट एरिया का भ्रमण कर चल रहे कार्यों का विस्तार से मुआयना किया। जिसके पश्चात उन्होंने बैठक लेकर परियोजना के हर हिस्से पर चल रहे काम और आगे की कार्ययोजना की बारी-बारी समीक्षा की। समीक्षा बैठक में मंदिर परिसर, प्रवेश द्वार, संग्रहालय, पर्यटक सुविधाओं से जुड़े निर्माण कार्यों के प्रोजेक्ट

प्लान के अनुसार बेस वर्क, परिसर की लैंडस्केपिंग व वृक्षारोपण, सरोवर के सौंदर्यीकरण जैसे बिंदुओं पर मैराथन समीक्षा हुई।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि यह परियोजना आने वाले कई सालों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है, इसलिए हर कार्य मजबूत, टिकाऊ और मानक अनुसार होना चाहिए। उन्होंने सख्त और स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए और इसके लिए पर्याप्त मशीनरी और मानव संसाधन बढ़ाया जाए। किसी भी स्थिति में कार्य में देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि किसी प्रकार की तकनीकी या अन्य कोई समस्या आती है तो उसकी जानकारी तुरंत दी जाए, आवश्यक काम प्रभावित नहीं होना चाहिए। समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री ने हर सोमवार होने वाली प्रगति मॉनिटरिंग की जानकारी ली और अब तक हुए कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से फील्ड में मौजूद रहें और निर्माण कार्य की लगातार निगरानी करें। उन्होंने पर्यटन विभाग के इंजीनियरों को भी निर्देशित किया कि वे निर्माण एजेंसियों को तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराएं ताकि कार्य की गति और गुणवत्ता दोनों बनी रहे। बैठक के दौरान मंदिर परिसर, सरोवर, मड़वा महल, छेरकी महल, रामचुआ तथा सरोदा डैम से जुड़े निर्माण कार्यों की भी विस्तार से समीक्षा की गई और उनकी प्रगति पर चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉरिडोर के प्रवेश द्वार, खंभों और दीवारों में फणी नागवंशी स्थापत्य शैली की स्पष्ट झलक दिखाई देनी चाहिए ताकि यहां आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक छत्तीसगढ़ की प्राचीन संस्कृति से जुड़ सकें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि द्वार पर स्थापित होने वाला नंदी प्रतिमा विशाल और आकर्षक हो जिससे परिसर का भव्य स्वरूप और अधिक प्रभावी दिखे। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने आदिवासी संग्रहालय के विकास और विस्तार पर भी जोर दिया और कहा कि भोरमदेव क्षेत्र की ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को संग्रहालय में प्रभावी तरीके से प्रदर्शित किया जाए। साथ ही मंदिर निर्माण की पूरी कथा और इतिहास को भी वहां दर्शाया जाए ताकि पर्यटकों को जानकारी मिल सके। उप मुख्यमंत्री ने स्वच्छता और सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिला और पुरुष शौचालय अलग-अलग और व्यवस्थित स्थानों पर बनाए जाएं तथा महिलाओं के लिए सुविधाजनक दूरी पर शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए पौधरोपण की पूरी तैयारी पहले से कर ली जाए।

औषधीय पौधों की खेती से आर्थिक उन्नति का बेहतर विकल्पः शुक्ला

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड द्वारा आज राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (एसएफआरटीई), रायपुर के परिसर में एक दिवसीय महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। धान की खेती के बदले औषधीय पौधों की खेती विषय पर केंद्रित इस कार्यशाला की अध्यक्षता बोर्ड के उपाध्यक्ष अंजय शुक्ला ने की।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए बोर्ड के उपाध्यक्ष अंजय शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए औषधीय व सुगंधित पौधों की खेती एक गेम-चेंजर साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि पारंपरिक धान की खेती में इनपुट कॉस्ट (लागत) लगातार बढ़ रही है और उसके मुकाबले शुद्ध लाभ अपेक्षाकृत कम होता है। इसके विपरीत, औषधीय पौधों की खेती में कम लागत और कम मेहनत में कई गुना अधिक लाभ कमाने की अपार संभावनाएं हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसानों को अब फसल विविधीकरण (क्रॉप डायवर्सिफिकेशन) को अपनाना होगा। राज्य सरकार दे रही है बाय-बैक और इनपुट सहायता की गारंटी: किसानों को प्रोत्साहित करने और उनके जोखिम को कम करने के लिए शुक्ला ने बोर्ड द्वारा दी जा रही विशेष सुविधाओं की जानकारी दी। इच्छुक किसानों को बोर्ड की तरफ से नि:शुल्क पौधे, उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावहारिक ज्ञान के लिए अध्ययन भ्रमण (एक्सपोजर विजिट) की सुविधा दी जा रही है। किसानों को फसल बेचने की चिंता से मुक्त करने के लिए बोर्ड द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठित व्यापारिक व औषधीय संस्थाओं से पूर्व अनुबंध (प्री कॉन्ट्रैक्ट) कराया जाता है, जिससे उत्पादन के तुरंत बाद तयशुदा कीमतों पर खरीदी सुनिश्चित हो सके।

तकनीकी सत्र- ब्राह्मी, वच और लेमनग्रास की वैज्ञानिक खेती पर जोर: कार्यशाला के तकनीकी व व्यावहारिक सत्र में बोर्ड के सलाहकार और सेवानिवृत्त वनमंडलाधिकारी डी.के.एस. चौहान ने विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।

प्रदेश में सम्पूर्ण सुशासन की सरकार की संकल्पना हो रहे साकारः देवांगन

रायपुर। प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम, आबकारी व श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने आज सोमवार को नगर पालिक निगम कोरबा के सर्वमंगलानगर जोनांतर्गत विकास नगर में आयोजित सुशासन तिहार शिविर को संबोधित करते हुये आज कहा कि प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर जनसमस्याओं के निराकरण हेतु सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है, मुख्यमंत्री श्री साय स्वयं गांव-गांव, गली-गली घूमकर जनसमस्याओं से रूबरू हो रहे हैं, उनका निराकरण करा रहे हैं तथा प्रदेश में सम्पूर्ण सुशासन की सरकार की संकल्पना को साकार कर रहे हैं।

यहां उल्लेखनीय है कि राज्य शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ कोरबा

जिले एवं नगर पालिक निगम केारबा क्षेत्र में भी सुशासन तिहार मनाया जा रहा है तथा इसके अंतर्गत शिविर आयोजित किये जा रहे हैं। आज निगम का सातवाँ व अंतिम सुशासन तिहार शिविर सर्वमंगला नगर जोनांतर्गत विकास नगर में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने शिविर में उपस्थिति प्रदान करते हुये महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत, सभापति श्री नूतन सिंह ठाकुर आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय तथा पार्षदों व जनप्रतिनिधियों के साथ शिविर में लगाये गये जिले के विभिन्न विभागों व नगर पालिक निगम केारबा के विभिन्न काउंटरों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर महापौर, सभापति व आयुक्त के साथ ही पार्षद नरेन्द्र देवांगन, भानुमति जायसवाल, रामाधार पटेल, आरती सिंह, प्रेमप्रकाश साहू, बहत्तर सिंह कंवर, मुकुंद सिंह कंवर, रामकुमार साहू, मनीष मिश्रा आदि जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। इस अवसर पर दिये गये अपने उद्बोधन में उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विगत 11 वर्षो के अपने कार्यकाल में देश का सम्मान विश्व स्तर पर बढ़ाया है, जिसके लिये हम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति दिल से आभार व्यक्त करते हैं, वहीं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय अपने कार्यो व योजनाओं से लगातार जनकल्याण का कार्य कर रहे हैं। उन्होने कहा कि हमारी सरकार जनहितकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर विश्वास रखती है तथा सरकार जो कहती है, वह करती भी है।

राजस्व प्रकरणों का तय समय-सीमा में हो निराकरणः वर्मा

रायपुर । राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने आज रायपुर तहसील कार्यालय और नवीन संभाग आयुक्त कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। मंत्री के इस अचानक दौरे से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान राजस्व मामलों के निपटारे में कछुआ गति और लापरवाही सामने आने पर मंत्री ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने आम जनता से जुड़े नामांतरण, त्रुटि सुधार, सीमांकन और बंटवारे जैसे संवेदनशील प्रकरणों में हो रहे विलंब को लेकर अधिकारियों को आड़े हाथों लिया और इन्हें शीघ्र निपटाने के कड़े निर्देश दिए। विशेष रूप से डायवर्सन (व्यपवर्तन) के मामलों में बेहद धीमी प्रगति पाए जाने पर मंत्री ने अनुविभागीय अधिकारी रायपुर को जमकर फटकार लगाई।

नरीक्षण के दौरान राजस्व मंत्री ने कार्यालय परिसर की साफ-सफाई की व्यवस्था का भी जायजा लिया। उन्होंने परिसर में फैली गंदगी और फाइलों के अव्यवस्थित रखरखाव पर अप्रसन्नता व्यक्त की। मंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि आम जनता की सुविधा के लिए कार्यालय में स्वच्छ वातावरण और बैठने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, साथ ही सभी शासकीय दस्तावेजों व फाइलों को पूरी तरह व्यवस्थित रखा जाए। तहसील कार्यालय की कार्यप्रणाली को बारीकी से समझने के लिए राजस्व मंत्री स्वयं भुइयां शाखा, कानूनगो शाखा,डब्ल्यूबीएन शाखा और मालजमादार शाखा पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने तहसीलदार और नायब तहसीलदार न्यायालयों का भी सघन निरीक्षण किया।

छग स्टेट पॉवर कंपनी करेगी अभा क्रिकेट और टेबल टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी

रायपुर। अखिल भारतीय विद्युत खेल नियंत्रण बोर्ड (एआईईएससीबी) की 48 वीं वार्षिक साधारण सभा की दो दिवसीय बैठक रविवार को संपन्न हुई। बैठक में आगामी वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज को अखिल भारतीय क्रिकेट और टेबल टेनिस प्रतियोगिता की मेजबानी सौंपी गई।23 और 24 मई को रायपुर में आयोजित दो दिवसीय बैठक में देश भर की विद्युत कंपनियों एवं विद्युत मंडलों के इस वर्ष के खेल कैलेंडर तथा वित्तीय लेखा - जोखा का अनुमोदन किया गया ।

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं छत्तीसगढ़ केंद्रीय क्रीड़ा एवं कला परिषद के अध्यक्ष श्री संजीव कुमार कटियार ने बैठक का शुभारंभ किया। इस अवसर

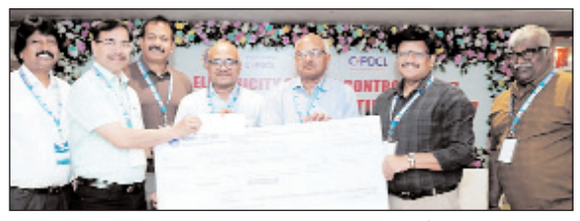

पर उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरत को पूरा करने वाले विद्युत कर्मियों के बीच एक सकारात्मक वातावरण निर्माण में खेल स्पर्धाओं का बड़ा महत्व है और ऐसे में सभी पॉवर कंपनियों को जिम्मेदारी पूर्वक राष्ट्रीय स्तर पर खेल गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए। उन्होंने एआईईएससीबी के पदाधिकारियों को बीते वर्ष अखिल भारतीय स्तर पर पॉवर सेक्टर कर्मियों के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के सफल संचालन के लिए बधाई दी। ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के कार्यपालक निदेशक श्री के एस मनोठिया ने बताया कि एजीएम के दौरान वित्त वर्ष 2025 -26 का लेखा - जोखा प्रस्तुत करने के साथ ही अन्य विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई जिससे आगामी वर्ष में अखिल भारतीय विद्युत खेल स्पर्धाओं का सफलतापूर्वक संचालन किया जा सके। 48 वीं एजीएम के दौरान पॉवर कंपनियों में विभिन्न स्तर पर भर्तियों में खेल कोटे में वृद्धि संबंधी विषय पर भी चर्चा की गई।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

भाजपा नहीं चाहती झीरम का सच सामने आयेः बैज

रायपुर। झीरम कांड की बरसी पर कांग्रेस ने अपने शहीद नेताओं का स्मरण करते हुए अनेकों सवाल खड़ा किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि झीरम घाटी कांड एक ऐसा कांड था जिसने कांग्रेस के नेतृत्व की एक पूरी पीढ़ी को ही समाप्त कर दिया था। स्वतंत्र भारत में हुई दुर्दान्त और हृदय विदारक घटना भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में डॉ. रमन सिंह के राज में घटित हुई थी इसके गुनाहगारों को सजा जरूर मिलनी

चाहिये। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा डरती है झीरम का सच सामने आ जायेगा तो वह बेनकाब हो जायेगी। रमन सिंह से बड़ा क्रूर शासक आजाद भारत में आज तक नहीं हुआ। एक साथ विपक्ष के 32 नेताओं की हत्या हो गयी और तत्कालीन सरकार सच सामने आने देन से रोकने में पूरी ताकत लगा रखी थी। भाजपा के बड़े नेता जीरम की जांच को रोकने लगातार कोशिशें करते रहे उसमें साफ है झीरम के पीछे तत्कालीन भाजपा सरकार की भूमिका संदिग्ध थी।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस सरकार ने झीरम हमले की जांच के लिये एसआईटी का गठन किया था लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार एनआईए से झीरम की फाइल एसआईटी को नहीं देने दिया।

डीजल-पेट्रोल का दाम बढ़ाना जन विरोधी निर्णयः शुक्ला

रायपुर। 12 दिन में तीसरी बार डीजल-पेट्रोल का दाम बढ़ाना जनता पर अत्याचार है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मोदी सरकार डीजल-पेट्रोल का दाम लगातार बढ़ाते जा रही है। डीजल-पेट्रोल के दामों में 87 पैसे पेट्रोल और डीजल पर 91 पैसे की बढ़ोत्तरी की गयी है। इसके पहले दो बार बढ़ोत्तरी हुई थी। पहले 3.30 पैसे फिर 95 पैसे इस बार 2.61 पैसे तथा 2.71 की बढ़ोत्तरी की गयी। अभी

तक 8.50 रू. से अधिक बढ़ाया जा चुका है। स संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मोदी सरकार डीजल-पेट्रोल के दाम में 20 रू. की बढ़ोत्तरी करना चाह रही। इसीलिए डीजल-पेट्रोल की कृत्रिम संकट पैदा की गयी है। पेट्रोल-डीजल दाम बढ़ाने के साथ पूरे दिन प्रदेश के अधिकांश पंपो में डीजल नहीं मिल रहा था। यह कृत्रिम संकट भाव बढ़ाने को सही ठहराने के उद्देश्य से किया गया है। जिस प्रकार पेट्रोलियम कंपनियां लगातार पेट्रोल, डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर रहे है। ऐसा लग रहा है मोदी सरकार ने पेट्रोलियम कंपनियों को जनता को लूटने की खुली छूट दे दी है। सरकार जब जनता के बजाय कंपनियों की नफा नुकसान की चिंता करे, तो जनता तो महंगाई की बोझ तले दबती जायेगी।

पूरे प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती से जनता परेशानः वंदना

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि बिजली के साथ भाजपा सरकार आने के बाद जनता को पूरे 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है।। पूरे प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती हो रही है। ढाई साल में विद्युत सरप्लस वाला छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कटौती का केंद्र बन गया है। कोई ऐसा दिन नहीं होता जब बिजली दो-चार घंटे के लिये बंद न हो, रात में तो बिजली की स्थिति तो और भयावह हो जाती है, घंटो बिजली गोल हो जाती है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता

वंदना राजपूत ने कहा कि भाजपा से न सरकार संभल पा रहा और न ही व्यवस्थायें। सरकार एक तो पूरे समय बिजली नहीं दे पा रही, ऊपर से उपभोक्ताओं पर महंगी बिजली का बोझ डाल रही है। प्रदेश के अनेक जिलों में तो पूरी रात बिजली कटौती हो रही है। भाजपा सरकार में आम जनता को मांग के अनुसार बिजली नहीं मिल रहा है। बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से शहर और गांव की जनता जूझ रहे हैं। मई माह में हर उपभोक्ता का बिजली बिल दो से तीन गुना ज्यादा आया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के दौरान 24 घंटा बिजली की आपूर्ति होती थी। गर्मी के दिनों में मांग बढ़ने पर दूसरे राज्यों से भी बिजली की खरीदी किया जाता था और आम जनता को 24 घंटा बिजली की आपूर्ति की जाती थी।

मुख्य सचिव ने ली बाढ़ नियंत्रण हाई पावर कमेटी की बैठक

रायपुर। आगामी मानसून के दौरान प्राकृतिक आपदाओं, विशेषकर बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा की गई तैयारियों की गहन समीक्षा की गई। राहत शिविरों के प्रबंधन से लेकर आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी आवश्यक पहलुओं पर व्यापक रणनीति तैयार की गई। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय (महानदी भवन) में राज्य स्तरीय उच्च स्तरीय बाढ़ नियंत्रण समिति की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई।मुख्य सचिव ने राज्य के सभी जिला कलेक्टर्स एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्षों को मानसून 2026 के मद्देनजर सुरक्षा और राहत व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। सभी कलेक्टर्स को आगामी 1 जून से प्रतिदिन वर्षा की स्थिति और उससे होने वाली संभावित क्षति की जानकारी अनिवार्य रूप से शासन को भेजनी होगी। प्रत्येक जिले में बाढ़ नियंत्रण के लिए विशेष नोडल अधिकारियों की नियुक्ति तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में जून माह में मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। आपदा के समय त्वरित सहायता और समन्वय के लिए राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष क्रियाशील कर दिया गया है।

खुले क्षेत्रों में न करें कुरबानी, सभी समाज की आस्था का रखें ध्यान : डॉ.सलीम राज

रायपुर। आगामी दिवस 28 मई 2026 गुरूवार को पूरे देष में ईद-उल-अज़हा का त्योहार मनाया जायेगा, ईद-उल-अज़हा की नमाज़ छत्तीसगढ़ प्रदेष में सुबह 06:00 बजे से लेकर 11:00 बजे तक प्रदेष की विभिन्न मस्जिद, ईदगाह में निर्धारित समय अनुसार अदा की जायेगी एवं ईद की मुबारकबाद दी जायेगी। यह

त्योहार मुस्लिम धर्म में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम व हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद में मनाया जाता है जिसमें दिनांक 28.05.2026 के सूर्योदय से लेकर 30.05.2026 सूर्यास्त तक मुस्लिम समाज के साहिबे निसाब व्यक्ति द्वारा कुरबानी की जाती है। पैगम्बर साहब ने भी हमें संदेष दिया है कि हम जिस देष में रहते हैं वहां के संविधान का हमें आदर करना चाहिये, हमारे आस-पास में निवास करने वाले हमारे भाईयों की आस्था का आदर करना चाहिये, जिससे समाज में आपसी भाईचारा, अमन कायम रहे, इस्लाम धर्म, कुरआन व हदीस भी हमें सभी धर्मों के प्रति आस्था, आपसी भाईचारा, मोहब्बत और साम्प्रदायिक सौहार्द का संदेष देते हैं।

मिनीमाता बांगो डिवीजन, कटघोरा एवं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

जशपुर के बगिया क्षेत्र के किसानों की बदलेगी तकदीर

रायपुर । जशपुर के बगिया क्षेत्र में कृषि एवं ग्रामीण विकास को नई दिशा प्रदान करने में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर एवं मिनीमाता बांगो डिवीजन, माचाडोली, कटघोरा के मध्य फार्मर रिलेशनशिप एजेंसी निर्धारण हेतु आज यहां एक समझौता (एमओयू) किए गया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल की उपस्थिति में संपन्न समझौता ज्ञापन पर श्री अखिलेश साहू, कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो डिवीजन, कटघोरा एवं डॉ. एस. एस. टुटेजा, निदेशक विस्तार सेवाएं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा

हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता जशपुर के बगिया क्षेत्र के किसानों को वैज्ञानिक कृषि तकनीकों से जोड़ते हुए उनकी आय वृद्धि, कृषि उत्पादन में सुधार एवं ग्रामीण कृषि व्यापार को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत मिनीमाता बांगो बांध के कमांड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 13 गांवों में विभिन्न कृषि विकास गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। इन गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु कृषि विज्ञान केन्द्र, जशपुर को नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। परियोजना के माध्यम से किसानों के खेतों का मृदा परीक्षण, फसल एवं वर्तमान कृषि स्थिति का विस्तृत सर्वेक्षण किया जाएगा। साथ ही किसानों एवं ग्रामीण समुदाय के मध्य परियोजना संबंधी जागरूकता निर्माण हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। किसानों के खेतों में वैज्ञानिक पद्धति से फसल प्रदर्शन कर आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया जाएगा ताकि किसान नवीन तकनीकों को अपनाकर बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकें। कृषकों को उन्नत कृषि आदान सामग्री जैसे उन्नत बीज, जैव उर्वरक एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त उद्यानिकी फसलों की उन्नत तकनीकों के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ उद्यानिकी फसलों हेतु उन्नत बीज, जैव उर्वरक एवं कृषि यंत्र भी उपलब्ध कराए जाएंगे। परियोजना का उद्देश्य किसानों को टिकाऊ एवं लाभकारी कृषि प्रणाली से जोड़ना है।

इस परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं एवं पानी कृषि मित्रों का प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे उन्हें कृषि आधारित रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। किसानों के लिए समय-समय पर प्रक्षेत्र दिवसों का आयोजन किया जाएगा, जहां विशेषज्ञों द्वारा आधुनिक कृषि तकनीकों, जल प्रबंधन, फसल विविधीकरण एवं बाजारोन्मुख खेती की जानकारी प्रदान की जाएगी।

चुनाव आयोग से मिलासूरजपुर मामले में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल

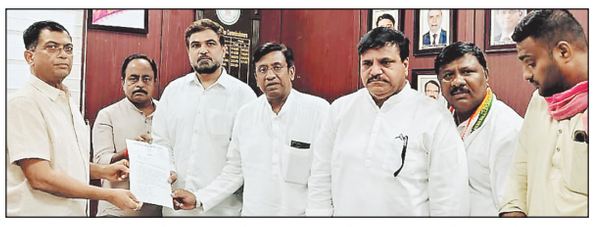

रायपुर। कांग्रेस पार्टी के चुनाव संचालन कर रहे जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री नरेन्द्र जैन के खिलाफ आर्म एक्ट के तहत फर्जी एफ.आई.आर. कर चुनाव कार्य को प्रभावित करने का प्रयास स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। जिसकी शिकायत को लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश चुनाव आयोग से मिला तथा ज्ञापन सौपा।

ज्ञापन में कहा गया है कि शिवनंदनपुर नगर पंचायत आम-निर्वाचन 2026 में भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए राजनैतिक दबाव बनाकर कांग्रेस पार्टी के चुनाव संचालन कर रहे जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री नरेन्द्र जैन के खिलाफ आर्म एक्ट के तहत फर्जी एफ.आई.आर. कर चुनाव कार्य को प्रभावित करने का प्रयास स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। जिसके विरोध में आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्री दीपक बैज जी के नेतृत्व में प्रकरण पर कार्यवाही हेतु सूरजपुर जिले के विश्रामपुर थाने का घेराव कर अनिश्चितकालिन धरने पर बैठें हैं ।कांग्रेस पार्टी इस ज्ञापन के माध्यम से आपसे आग्रह करती है कि, अविलंब इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए उक्त स्थानीय थाना प्रभारी पर कड़ी कार्यवाही करते हुए निलंबित करने का कश्ट करेंगे ।प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री सकलेन कामदार, जिला शहर अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन, जिला ग्रामीण अध्यक्ष राजेन्द्र पप्पू बंजारे, पूर्व महापौर प्रमोद दुबे, पूर्व महामंत्री पंकज शर्मा, असंगठित क्षेत्र समस्या निवारण प्रकोष्ठ अध्यक्ष मोहम्मद सिद्दीक शामिल हुये।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.